सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 75, नई दिल्ली, रविवार 25 मई 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

आदत किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, अति होने पर हमेशा कष्टदायक होती है।

03 दिल्ली में अब पेंशन लेने के लिए ये कागज जरूरी, इन लोगों के काटे जाएंगे नाम
06 सेमीकंडक्टर उद्योग में उभरते कैरियर पथ
08 धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

अब दूर से ही नजर आएंगी डीटीसी की बसें, दिल्ली में चलने वाली देवी बसों में बड़ा बदलाव

दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही इलेक्ट्रिक बसों का रंग अब बदलेगा। ये बसें नारंगी पीले और हरे रंग में रंगी जाएंगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में दो आदेश जारी किए हैं। पहले नारंगी रंग रखने की बात थी लेकिन बाद में तीन रंगों का निर्णय लिया गया। योजना के तहत कुल 2080 बसें शामिल होंगी जिन्हें नए रंगों में रंगा जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली में सड़कों पर दौड़ने लगी डीईवीआई (दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटर कनेक्टर) बसों का रंग बदलेगा। फिलहाल ये ई-बसें एक ही रंग की हैं। अब ये बसें तीन रंगों में नजर आएंगी। इन बसों को गहरे नारंगी, पीले और हरे रंग में रंगा जाएगा।

दिल्ली में 400 छोटी इलेक्ट्रिक बसें चल रही

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन रंगों के बाद ये बसें दूर से ही नजर आएंगी और लोगों को इनका फायदा मिलेगा। फिलहाल दिल्ली में 400 छोटी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। बसों का रंग बदलने को लेकर परिवहन विभाग ने आठ दिन के अंदर दो आदेश जारी किए हैं।

इस संबंध में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह की मंजूरी पर पहला आदेश 14 मई को जारी हुआ था, जिसमें रंग बदलने की बात थी, लेकिन रंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सूत्रों का कहना है कि पहले इन बसों का रंग डीएमटीएस की नॉन एसी बसों की तरह नारंगी रखने की बात थी, लेकिन बाद में 19 मई को दूसरा आदेश जारी हुआ, जिसमें इन बसों को तीन रंगों में रखने का निर्णय लिया गया।

योजना के तहत आएगी कुल 2080 बसें

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जल्द ही इन बसों के नए रंग को लेकर मॉडल उपलब्ध कराया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद चल रही 400 नौ मीटर की बसें इन्हीं रंगों में रंगी जाएंगी। इसके अलावा अब जो भी नौ मीटर की ई-बसें आएंगी, वे तीन रंगों- हरा, नारंगी और पीला- की होंगी। इस योजना के तहत कुल 2080 बसें आनी हैं।

आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली की सड़कों

पर लाल, हरे, नारंगी और नीले रंग की 12 मीटर की बसें चलती हैं। इसमें डीटीसी की एसी बसें अभी सिर्फ लाल रंग की हैं और नॉन एसी बसें हरे रंग की हैं। ये बसें 2009-2010 में बड़ी संख्या में आनी शुरू हुईं।

वहीं, नारंगी रंग की बसें क्लस्टर सेवा के तहत चलने वाली स्टैंडर्ड फ्लोर बसें हैं। ये बसें भी पिछले कई सालों से दिल्ली में चल रही हैं। पिछले साल आधुनिक सुविधाओं से लैस नीले रंग की लो फ्लोर एसी बसें क्लस्टर और डीटीसी सेवा के तहत आईं।

दिल्ली मेट्रो के 75 हजार यात्रियों ने किया डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल, जानें फायदे और सुविधाएं

दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू होने से यात्रियों को सामान रखने की सुविधा मिली है। पिछले डेढ़ साल में करीब 75 हजार यात्रियों ने २१६ स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल किया है। डीएमआरसी ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है ताकि यात्री सफर के दौरान सामान खरीद सकें। वर्तमान में २१६ स्टेशनों पर १९२०० डिजिटल लॉकर लगाए गए हैं।

नई दिल्ली। मेट्रो स्टेशनों पर डिजिटल पार्सल लॉकर सुविधा शुरू होने से यात्रियों के लिए जरूरत पड़ने पर अपना सामान रखना आसान हो गया है। यही वजह है कि डेढ़ साल में मेट्रो में सफर करने वाले करीब 75 हजार यात्रियों ने २१६ स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल किया है। यात्रियों ने अपना सामान इस लॉकर में रखा।

इस समय एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क ३९३ किलोमीटर है और २४९ स्टेशन हैं। मेट्रो में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग का चलन भी बढ़ा है। इसे देखते हुए डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के मोबिलिटम २.० एप के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। ताकि मेट्रो में सफर के दौरान यात्री अपनी जरूरत का सामान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ले सकें और गंतव्य स्टेशन पर उतरने के बाद सामान लेकर घर जा सकें। इसे ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने नवंबर २०२३ में डिजिटल लॉकर शुरू किए थे। इस समय २१६ स्टेशनों पर कुल 19,200 डिजिटल लॉकर लगाए जा चुके हैं। प्रत्येक स्टेशन पर 83 से 90 लॉकर लगाए जाते हैं। इसमें छोटे, मध्यम और बड़े साइज के पैकेट रखे जा सकते हैं। लॉकर बुक करते समय प्राप्त पिन कोड का उपयोग करके लॉकर का उपयोग किया जा सकता है। यह लॉकर पूरी तरह से डिजिटल है। इसे वाबी से बंद नहीं किया जा सकता।

15 मिनट में हटाई जाएंगी खराब बसें, डीटीसी ने किया ये काम

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने बसों की खराबी से होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए नई एसओपी लागू की है। अब खराब बसें 15 मिनट में हटाई जाएंगी जिसके लिए मुख्य स्थानों पर क्यूआरटी और क्रेन तैनात होंगे। पुरानी बसों के कारण हर दिन 100 से ज्यादा बसें खराब होती हैं। नई एसओपी में क्यूआरटी 5 मिनट में पहुंचकर 15 मिनट में बस को डिपो पहुंचाएगी।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली में खराब बसों से होने वाली परेशानियों को खत्म करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। अब खराब बसों को 15 मिनट में हटाया जा सकेगा। इसके लिए 30 प्रमुख स्थानों पर क्रेन और क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) तैनात की जाएंगी।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, हर दिन 100-123 बसें खराब हो जाती हैं, खास तौर पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट, मिंटो ब्रिज, सराय काले खां, आईटीओ, एम्स फ्लाईओवर और धौला कुआं जैसे इलाकों में। समस्या की मुख्य वजह यह है कि 2010 में खरीदी गई बसें लगभग पुरानी हो चुकी हैं।

नए एसओपी के तहत, खराब होने की सूचना पर क्यूआरटी पांच मिनट में प्रतिक्रिया देगी और बस को 15 मिनट में नजदीकी डिपो तक

पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 24x7 कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो जलभराव पर भी नजर रखेगा।

सहायता के लिए 100 फील्ड ऑपरेशन टीमें और 70 बाइक मोबाइल टीमें तैनात की गई हैं, जो ब्रेक फेल होने जैसी समस्याओं को मौके पर ही ठीक करेंगी। डीटीसी का यह कदम दिल्ली की सड़कों पर यातायात व्यवस्था को सुधारने में मददगार साबित होगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आईएसबीटी कश्मीरी गेट, मिंटो ब्रिज, सराय काले खां, आईटीओ, एम्स फ्लाईओवर और धौला कुआं जैसे इलाकों में रोजाना कम से कम 100-123 बसें खराब हो जाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए नई एसओपी जारी की गई है। नई एसओपी जारी

एसओपी के अनुसार गठित क्यूआरटी को ब्रेकडाउन अलर्ट मिलने के पांच मिनट के भीतर जवाब देना होगा। डीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में परिवहन ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

निगम का मुख्य फोकस उन बसों को हटाने पर है जिनकी सेवा अवधि लगभग समाप्त हो चुकी है और वे इस्तेमाल के अंतिम चरण में हैं। इसके अलावा दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की सेवा बढ़ाई जाएगी। दिल्ली सरकार बस डिपो को व्यावसायिक केंद्र बनाने की योजना बना रही है। इससे दिल्ली को 2600 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू की नई पहल, हाइड्रोलिक एंटी-स्मॉग गन वाहन तैनात

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई पहल की है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की कि डीएसआईआईडीसी दिल्ली के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में आठ जीपीएस-सक्षम एंटी-स्मॉग गन ट्रक तैनात करेगा। यह वाहन वायु प्रदूषण को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेंगे। यह परियोजना शहरी जीवन के लिए पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को घोषणा की कि वायु प्रदूषण से निपटने के सतत प्रयास में, डीएसआईआईडीसी दिल्ली के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में जीपीएस-सक्षम वाटर स्प्रिंकलर से लैस आठ उन्नत हाइड्रोलिक एंटी-स्मॉग गन ट्रक-माउंटेड वाहन तैनात कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य वायुजनित धूल प्रदूषण को काफी कम करना और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

इन आठ नए जीपीएस-सक्षम एंटी-स्मॉग गन वाहनों को जून से पटपड़गंज, ओखला फेज III, ए ब्लॉक और एस ब्लॉक फेज II, झिलमिल, नांगलोई, उद्योग विहार, बादली और भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दो अतिरिक्त एंटी-स्मॉग गन वाहन भी रखे गए हैं।

प्रत्येक हाइड्रोलिक एंटी-स्मॉग गन वाहन सीएनजी से संचालित है। इसमें एक एंटी-स्मॉग गन है जो 330 डिग्री घुमाव के साथ क्षैतिज रूप से 30 मीटर तक महीन स्मॉग का छिड़काव करने में सक्षम है, जिससे व्यापक और प्रभावी क्षेत्र कवरेज सुनिश्चित होता है।

ट्रकों में सड़कों पर एक साथ पानी का छिड़काव करने के लिए उनकी चौड़ाई में फैले क्षैतिज स्प्रिंकलर भी लगे हैं, जिससे प्रति घंटे 1,500 लीटर पानी की खपत होती है।

हाइड्रोलिक एंटी-स्मॉग गन वाहन दो शिफ्टों में आठ घंटे तक काम करेगा - एक शिफ्ट सुबह 3 बजे से सुबह 7 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर में चार घंटे की होगी। इससे औद्योगिक प्रदूषण पर लगाम लगने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली में स्वच्छ हवा में योगदान मिलेगा।

यह परियोजना, जो मानसून अवधि को छोड़कर दस महीने तक चलेगी, शहरी जीवन के लिए पर्यावरण के अनुकूल समाधान लागू करने की दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

सिरसा ने आगे कहा, "हमारी सरकार पर्यावरण की रक्षा करते हुए औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम औद्योगिक कचरे को कम करने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं ताकि उद्योग जिम्मेदारी से बढ़ सकें।"

"कोविड को देखते हुए जारी किए गए दिशा निर्देश" जाने

दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
सार्वजनिक स्वास्थ्य विंग-IV
तृतीय तल, डीजीडी बिल्डिंग, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092
ईमेलः phw4delhi@yahoo.com

एफ.नं.567/डीजीएचएस/पीएचडब्ल्यू-IV/कोविड-19/एमओएचएफडब्ल्यू दिशानिर्देश/2021/एसएसएच फुट/508-518, दिनांकः 23/5/25

परामर्शी

हाल ही में COVID-19 मामलों में हुई वृद्धि को देखते हुए, यह दोहराया जाता है कि सभी सरकारी/निजी अस्पतालों के चिकित्सा निदेशकों/चिकित्सा अधीक्षकों/प्रशासकों द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिए:

1. बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता के मामले में अस्पताल की तैयारी सुनिश्चित करें। वेंटिलेटर, बाई-पैप, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीएसए आदि सभी उपकरण काम करने की स्थिति में हैं।

2. समर्पित कर्मचारियों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है।

3. सभी स्वास्थ्य सुविधाओं (ओपीडी/आईपीडी) में इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी (एसएआरआई) के मामलों की रिपोर्टिंग दैनिक आधार पर एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफ़ॉर्म (आईएचआईपी) पोर्टल पर की जानी चाहिए। पुष्टि किए गए इन्फ्लूएंजा और कोविड-19 मामलों को भी एल फॉर्म के तहत आईएचआईपी पर रिपोर्ट किया जा सकता है।

4. दिल्ली राज्य स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन पोर्टल पर सभी मापदंडों की दैनिक रिपोर्टिंग।

5. कोविड-19 परीक्षण दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्याप्त परीक्षण। 5% ILI मामलों और 100% SARI मामलों की COVID-19 जांच सुनिश्चित करें। परीक्षण के लिए ICMR दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

6. सभी पॉजिटिव कोविड-19 नमूनों को संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के लिए लोकनायक अस्पताल भेजें, ताकि नए वेरिएंट का समय पर पता लगाया जा सके, यदि कोई हो और डब्ल्यूजीएस के लिए भेजे गए नमूनों की संख्या राज्य निगरानी इकाई के साथ साझा की जा सके।

7. अस्पताल परिसर/स्वास्थ्य सुविधाओं में मास्क पहनने सहित श्वसन शिष्टाचार का पालन किया जा रहा है (सलाह संलग्न है)।

इसे सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाएगा।

विशेष सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

एफ.सं. 567/डीजीएचएस/पीएचडब्ल्यू-IV/कोविड-19/एमओएचएफडब्ल्यू दिशानिर्देश/2021/sshfw1/508-518, दिनांकः 23/5/25

में कॉपीः

1. दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के एमडी/एमएस
2. एमएस (नर्सिंग होम सेल), डीटीई
जीएचएस, जीएनसीटीडी के माध्यम से सभी निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम के एमडी/एमएस/प्रशासक।

जानकारी के लिए कॉपी करें:

1. माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के सचिव को सूचनार्थ।
2. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), जीएनसीटीडी
3. एमडी, डीएसएचएम
4. निदेशक, डीजीएचएस, जीएनसीटीडी
5. सभी जिला मजिस्ट्रेट, जीएनसीटीडी
6. सभी मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, जीएनसीटीडी
7. सभी जिला निगरानी अधिकारी, जीएनसीटीडी
8. डॉ. रितु, सार्वजनिक स्वास्थ्य - IV, डीजीएचएस, जीएनसीटीडी
9. कार्यालय प्रति

विशेष सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

"महिलाओं की संसद और न्यायपालिका में भागीदारी: चिंतनशील विश्लेषण"

भारत में 77 सालों का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी के मामले में हम कई मोर्चों पर अभी भी पीछे हैं। विशेष रूप से संसद और न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व चिंतनीय स्तर पर है। जबकि न्यायपालिका में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, संसद में उनका प्रतिनिधित्व अब भी अप्रत्याशित और बेहद कम है। इस संदर्भ में, यह आवश्यक है कि हम विधिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इस मुद्दे का गहन और चिंतनशील विश्लेषण करें।

भारत में संविधान ने महिलाओं के लिए समानता और स्वतंत्रता के अधिकार सुनिश्चित किए हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये अधिकार पूरी तरह से साकार नहीं हो पाए हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत महिलाओं को विशेष संरक्षण देने का प्रावधान है, और अनुच्छेद 16 में समान रोजगार के अवसर का अधिकार है। फिर भी, संसद और न्यायपालिका में महिलाओं का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है।

महिलाओं के लिए विधायिका में आरक्षण के सवाल पर बहस हो रही है। महिला आरक्षण विधेयक पिछले कुछ वर्षों से संसद में अटका हुआ है, जो महिला सांसदों के लिए एक निश्चित प्रतिशत सीटों का आरक्षण प्रदान करने की बात करता है। अगर यह विधेयक पास होता है, तो यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हालांकि, जब तक यह कदम नहीं उठाया जाता, तब तक महिलाओं को विधायिका में समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा।

वहीं, न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती संख्या से न्यायिक निर्णयों में विविधता और संवेदनशीलता का समावेश हो सकता है, जैसा कि हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में देखा गया है। लेकिन महिलाओं की नियुक्ति, खासकर उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में, समानता के सिद्धांत को साकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में, भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित है। हालांकि, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था पंचायतों और स्थानीय निकायों में है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या लगातार बहुत कम रही है। यह न केवल महिलाओं की आवाज को कम करता है, बल्कि नीति निर्धारण में उनके दृष्टिकोण के अभाव को भी जन्म देता है।

महिला आरक्षण बिल के आने के बावजूद, उसकी स्वीकृति में राजनीतिक दलों के भीतर सहमति का अभाव है। इस राजनीतिक जटिलता को हल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि महिलाओं की संख्या संसद में जनसंख्या के अनुपात में हो, ताकि नीति निर्माण में उनका बराबरी का हिस्सा सुनिश्चित किया जा सके। यह महज एक सांविधानिक अधिकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक आवश्यकता है, जो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा।

महिलाओं का संसद और न्यायपालिका में अधिक प्रतिनिधित्व, न केवल सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद होगा। शोध यह दर्शाते हैं कि जहां महिलाओं की अधिक भागीदारी होती है, वहां निर्णय और नीति निर्माण में सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं।

जब महिलाएं राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होती हैं, तो उनके द्वारा किए गए निर्णय देश की अर्थव्यवस्था पर गहरे प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, महिला कार्यबल के लिए बेहतर नीतियां, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम, और महिलाओं के अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशीलता सुनिश्चित हो सकती है। महिलाओं की उपेक्षा से देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है, क्योंकि आधी आबादी का पूरा योगदान केवल इसलिए निष्क्रिय हो जाता है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती।

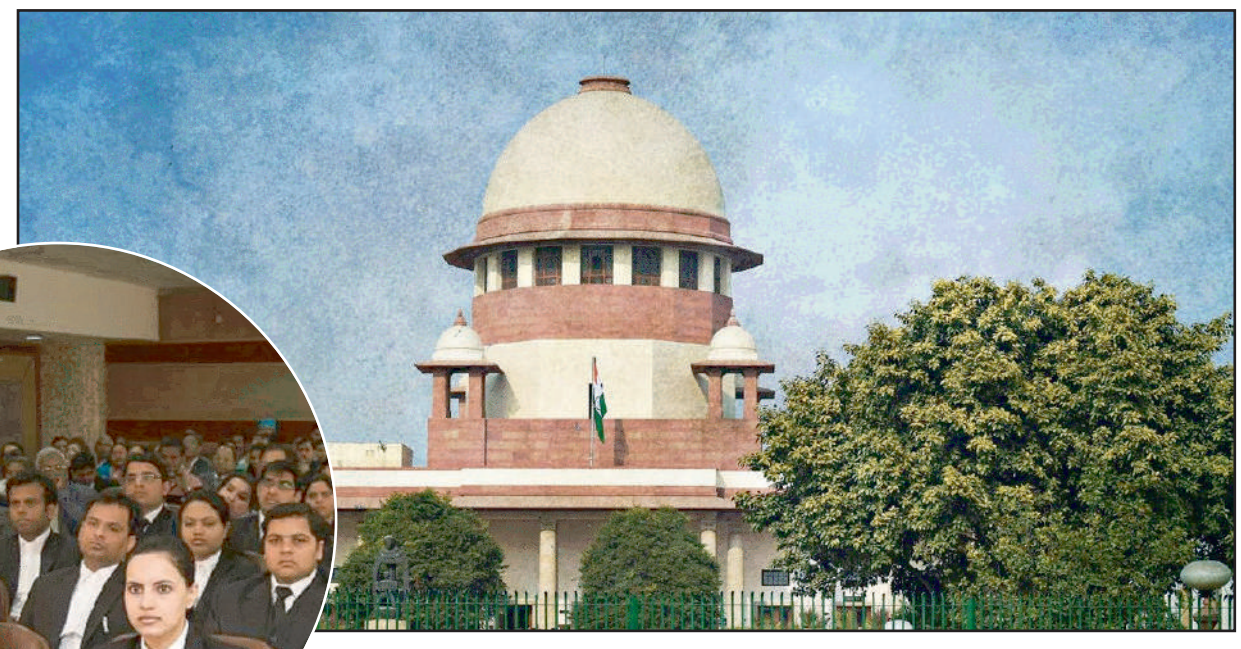

सामाजिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि महिलाएं हमेशा से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही हैं, और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा देने की दिशा में बहुत काम किया गया है। फिर भी, भारतीय समाज में महिलाओं को निर्णय लेने में समान अवसर नहीं मिलते। यह समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच असमानताओं को बढ़ाता है।

सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक है कि महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए। यह न केवल महिलाओं के लिए न्याय का एक मार्ग है, बल्कि यह समाज के सभी वर्गों में समानता और समावेशिता की भावना को बढ़ाता है। महिलाओं का संसद और न्यायपालिका में अधिक प्रतिनिधित्व, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हो सकता है। जब महिलाएं उच्च पदों पर पहुंचती हैं, तो वे न केवल खुद को, बल्कि अन्य महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी अवसरों का निर्माण करती हैं।

वर्तमान स्थिति में, जबकि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत बहुत कम है। यह सही है कि लैंगिक समानता की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन विधिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि महिलाओं को संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिले। महिला आरक्षण विधेयक एक आवश्यक कदम है, लेकिन यह कदम तभी प्रभावी होगा जब राजनीतिक दल और समाज इसे सही तरीके से समझें और स्वीकारें।

अगर हम एक सशक्त और समावेशी लोकतंत्र चाहते हैं, तो महिलाओं की भागीदारी को समान रूप से बढ़ाना होगा। सिर्फ न्यायपालिका तक सीमित रहकर हम लैंगिक समानता का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। यह समय की मांग है कि संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को जनसंख्या के समानुपात में बढ़ाया जाए, ताकि न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके, बल्कि समाज का हर वर्ग, हर समुदाय अपनी आवाज़ उठा सके।

मृत्यु के पश्चात मनुष्य 5 वस्तुएं साथ लेकर जाता हैं...

01.कामना :

यदि मृत्य के समय हमारे मन मे किसी वस्तु विशेष के प्रति कोई आसक्ति शेष रह जाती है । कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। कोई अपूर्ण कामना रह जाती है तो मरणोपरांत वही कामना उस जीवात्मा के साथ जाती है।

02.वासना :

वासना कामना की साथी है। वासना का अर्थ केवल शारिरिक भोग से नही अपितु इस संसार मे भोगे हुए हर उस सुख से है। जो उस जीवात्मा को आनन्दित करता है। फिर वो घर हो, पैसा हो, गाड़ी हो, रूतबा हो या शौर्य। मृत्यु के बाद भी ये अधूरी वासनाएं मनुष्य के साथ ही जाती हैं और मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है।

03.कर्म :

मृत्यु के बाद हमारे द्वारा किये गए कर्म चाहे वो सुकर्म हो या कुकर्म हमारे साथ ही जाता है। मरणोपरांत जीवात्मा अपने द्वारा किये गए कर्मो की पूंजी साथ ले जाता है। जिस हिसाब किताब द्वारा उस जीवात्मा का यानी हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है।

04.कर्ज़ :

यदि हमने मनुष्य जीवन मे कभी भी किसी प्रकार का ऋण लिया हो, तो उस ऋण को यथा सम्भव उतार देना चाहिए। ताकि मरणोपरांत इस लोक से उस ऋण को उस लोक में अपने साथ न ले जाना पड़े।

05.पुण्य :

हमारे द्वारा किये गए दान-दक्षिणा व परमार्थ के कार्य ही हमारे पुण्यों की पूंजी होती है। इसलिए हमें समय-समय पर अपने सामर्थ्य अनुसार दान-दक्षिणा एवं परमार्थ और परोपकार अवश्य ही करने चाहिए।

इन्ही पांचों वस्तुओं से ही मनुष्य का परलोक जाने पर अगले जन्म की प्रक्रिया का चयन किया जाता है।

ओ म त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को 5 ऋण चुकाने होते हैं...

01.माता का ऋण

02.पिता का ऋण

03.गुरु का ऋण

04.धरती का ऋण

05.धर्म का ऋण

01.माता का ऋण चुकाने के लिए कन्या दान करना चाहिए।

02.पिता का ऋण चुकाने के लिए संतान उत्पति करनी चाहिए।

03.गुरु का ऋण चुकाने के लिए लोगों को शिक्षित करना चाहिए।

04.धरती का ऋण चुकाने के लिए कृषि करना चाहिए या पेड़ लगाना चाहिए।

05.धर्म का ऋण चुकाने के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए।

वैदिक शिक्षा, अध्यात्म व धर्म का प्रचार प्रसार करें, विश्व की आधिकांश समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी.

धर्मो रक्षति रक्षितः...

आपके शरीर मे प्रोटीन की कमी कोने-कोने से खून छीन लेती है...

चिकन-मटन छोड़कर खाएं ये 10 सिम्पल लेकिन सुपर फूड, शरीर पर चढ़ेगा माँस

प्रोटीन डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां...

खाने में प्रोटीन ना होने की वजह से मसल्स खत्म होने लगती हैं।

इसकी वजह से कुपोषण होता है जो एनीमिया को बढ़ाता है।

दोनों समस्याओं का साथ में इलाज करने के लिए इन फूड्स का सेवन करें।

प्रोटीन की कमी से सूख जाएगा खून...

प्रोटीन की कमी से मरास्मस की बीमारी होती है।

इसमें प्रोटीन ना लेने से कुपोषण हो जाता है।

इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स भी कम होने लगती हैं।

जो खून की कमी को बढ़ावा देती हैं।

इस बीमारी में प्रोटीन देने वाला चिकन, मटन और अंडे से ज्यादा फायदेमंद दूसरे फूड होते हैं, जिनमें प्रोटीन के साथ आयरन भी होता है।

(1). पालक...

पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है जो थकान और कमजोरी मिटा देती है।

यूएसडीए के मुताबिक पालक के पत्तों में आयरन और प्रोटीन दोनों होता है।

यह कैल्शियम का भी स्त्रोत होता है।

(2). फलियाँ...

फलियाँ बेस्ट वेजिटेरियन फूड्स में से एक हैं।

इसके अंदर दालें, छोले और सोयाबीन आती है।

ये फूड्स मरास्मस की बीमारी दूर करने के लिए दोनों पोषक तत्व देते हैं।

(3). कद्दू के बीज...

अगली बार कद्दू के बीज फेंकने की गलती ना करें।

इन्हें सुखाकर भून लें और खाएं।

ये छोटे से बीज शरीर में प्रोटीन के साथ आयरन की भरमार कर सकते हैं।

(4). क्विनोआ...

क्विनोआ एक हाई प्रोटीन फूड है।

जो रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है।

इसकी खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं।

सलाद और स्मूदी में भी इसे डाला जाता है।

(5). ब्रोकली...

ब्रोकली एक सुपरफूड माना जाता है।

इसमें कैंसर से बचाने वाले गुण होते हैं।

साथ ही एनीमिया, थकान, कमजोरी जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है।

(6). टोफू...

टोफू दिखने में पनीर की तरह होता है मगर यह दूध से नहीं बनता।

इसे सोयाबीन से तैयार किया जाता है।

यह एक हाई प्रोटीन और हाई आयरन फूड है।

लैक्टोज इनटॉलरेंट भी इसका सेवन आराम से कर सकते हैं।

(7). डार्क चॉकलेट...

डॉर्क चॉकलेट महिलाओं को काफी पसंद आती है।

यह आयरन की कमी को दूर कर सकती है।

इसमें थोड़ा प्रोटीन भी होता है।

इसे खाकर मूड बेहतर बनता है।

मगर डायबिटीज में इसका सेवन करने से बचें।

(8). मक्के का आटा...

अगर आपको मक्के की रोटी खाना पसंद है तो हम एक और कारण दे रहे हैं।

यह कुपोषण और एनीमिया की बीमारी को खत्म कर सकती है।

पालक के साग के साथ इसका कॉम्बिनेशन काफी पावरफुल बनता है।

(9). ओट्स...

ओट्स से प्रोटीन, आयरन और फाइबर मिलता है।

इस वजह से वजन कम करने के साथ आयरन और प्रोटीन की कमी में इसका सेवन करें।

यह शरीर के लिए काफी हेल्दी फूड है।

(10). मटर...

मटर के दाने कमजोरी और थकान का इलाज कर सकते हैं।

यह आपके सूखे शरीर पर मांस चढ़ाते हैं।

इनमें प्रोटीन और आयरन की भरमार होती है।

विश्व थायरॉइड दिवस

विश्व थायराइड दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जो हर साल 25 मई को मनाया जाता है , जिसका उद्देश्य थायराइड रोग के बोझ, रोगी के अनुभव और थायराइड बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और उपचार के लिए प्रतिबद्ध सभी लोगों को मान्यता देना है। थायरॉइड रोग शायद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रचलित अंतःस्रावी विकारों में से एक है; भारत भी इसका अपवाद नहीं है। थायरॉइड रोग पर किए गए विभिन्न अध्ययनों से अनुमान लगाया गया है कि लगभग 4.2 करोड़ भारतीय इससे प्रभावित हैं।

विश्व थायराइड दिवस (WTD) का महत्व थायरॉयड ग्रंथि थायरॉयड हार्मोन का उत्पादन करती है जो सामान्य वृद्धि और ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक है। थायरॉयड डिसफंक्शन आम है, आसानी से पहचाना जा सकता है और आसानी से इलाज योग्य है, लेकिन अगर इसका निदान नहीं किया जाता है या इसका इलाज नहीं किया जाता है, तो इसके गंभीर प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका से लेकर मध्य अफ्रीका तक दुनिया भर में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग आयोडीन की कमी वाले इलाकों में रहते हैं। आयोडीन थायराइड हार्मोन के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसका वितरण वैश्विक स्तर पर असमान है और दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में यह और भी कम है। आयोडीन की कमी वाले लोगों में, थायरॉयड की शिथिलता सबसे आम तौर पर थायरॉयड ऑटोइम्यूनिटी के कारण होती है - जिसमें ग्रेव्स रोग, हाशिमोटो थायरॉयडिटिस और प्रसवोत्तर थायरॉयडिटिस शामिल है जिसमें थायरॉयड-विशिष्ट ऑटोरिएक्टिव एंटीबॉडीज शामिल हैं। आयोडीन की कमी और अधिकता दोनों ही हाइपोथायरायडिज्म के साथ-साथ हाइपरथायरायडिज्म का कारण बन सकते हैं ।

महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि 1% पुरुषों और 5% महिलाओं में चिकित्सकीय रूप से पता लगाने योग्य थायरॉइड नोड्यूल्स पाए जाते हैं, तथा उम्र बढ़ने के साथ-साथ आयोडीन की कमी वाले समुदायों में इसका

प्रचलन बढ़ता जाता है।

इस निराशाजनक समय में, थायरॉइड रोगों के बारे में जागरूकता को उजागर करने और उस पर ज़ोर देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करना और उसे सौंपना ज़रूरी है। ऐसा करने से स्क्रीनिंग, निदान, उपचार और, यदि संभव हो तो, इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी का प्रसार तेज़ी से होता है। विश्व थायरॉइड दिवस अपनी बढ़ती लोकप्रियता के साथ उपर्युक्त उक्तियों को सफलतापूर्वक प्राप्त करता है।

विश्व थायराइड दिवस (WTD) का इतिहास सितंबर 2007 में थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल की वार्षिक आम बैठक के दौरान, 25 मई को ₹विश्व थायराइड दिवस₹ मनाने का निर्णय लिया गया। पहला विश्व थायराइड दिवस 2008 में मनाया गया था, और हालांकि थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया, लेकिन विभिन्न सदस्य संगठन दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यूरोपीय थायरॉइड एसोसिएशन ने एसोसिएशन की वर्षगांठ मनाने के लिए 25 मई, 2008 को पहला ₹यूरोपीय थायरॉइड दिवस₹ मनाने की भी घोषणा की, तथा यूरोप में थायरॉइड समूहों और नेटवर्क को उस दिन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

थायरॉइड रोगों के प्रकार थायरॉयड रोग अपने निदान, उपचार और दृश्यता में अद्वितीय हैं। प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रारंभिक निदान और उपचार महत्वपूर्ण हैं। पांच सबसे महत्वपूर्ण थायरॉयड रोगों में हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म, गोइटर / आयोडीन की कमी से होने वाले विकार, हाशिमोटो थायरॉयडिटिस और थायरॉयड कैंसर शामिल हैं।

हाइपोथायरायडिज्म (थायराइड हार्मोन का कम उत्पादन): यह सभी उम्र के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। जन्मजात हाइपोथायरायडिज्म का शीघ्र निदान और मस्तिष्क क्षति को रोकने के लिए उपचार की आवश्यकता होती है, जो भारत में आम है, 2640 नवजात शिशुओं में से 1 में होता है। जागरूकता और स्क्रीनिंग कार्यक्रमों की कमी निदान में देरी के लिए योगदान करने वाले कारक हैं।

हाइपरथायरायडिज्म (थायराइड हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाना): यह थायरॉयड ग्रंथि के अत्यधिक सक्रिय होने के कारण होता है, जो शरीर के चयापचय को तेज कर देता है। हाइपरथायरायडिज्म के लक्षणों में वजन कम होना, हाथ कांपना, तेज़ या अनियमित दिल की धड़कन आदि शामिल हो सकते हैं।

गण्डमाला (बढ़ी हुई थायरॉयड ग्रंथि , थायरॉयड कार्यात्मक परिवर्तन से जुड़ी हो सकती है/नहीं भी हो सकती है): भारतीय शोध ने आयोडीन की कमी और स्थानिक घेंघा रोग के बीच एक संबंध स्थापित किया है, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में। आयोडीन की कमी नवजात शिशुओं में हाइपोथायरायडिज्म से जुड़ी पाई गई, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा नमक आयोडीनीकरण कार्यक्रम लागू किया गया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जन्मजात हाइपोथायरायडिज्म के प्रचलन को कम करने में सफल रहा है।

हाशिमोटो थायरायडाइटिस (जिसे हाशिमोटो रोग भी कहा जाता है) - एक स्वप्रतिरक्षी रोग जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाएं थायरॉयड ग्रंथि पर हमला करती हैं): एक भारतीय अध्ययन में पाया गया कि गण्डमाला से पीड़ित लड़कियों में से 7.5% में किशोर स्वप्रतिरक्षी थायरायडाइटिस (जिसमें हाशिमोटो थायरायडाइटिस भी शामिल है) था।

थायरॉयड कैंसर : एक विकार जिसमें थायरॉयड ग्रंथि के ऊतकों में घातक (कैंसर) कोशिकाएं विकसित होती हैं। थायरॉयड नोड्यूल अक्सर होते हैं; हालांकि, वे हमेशा कैंसर नहीं होते हैं। थायरॉयड कैंसर के कई रूप हैं। थायरॉयड कैंसर का जोखिम उम्र, लिंग और विकिरण जोखिम से प्रभावित हो सकता है।

थायरॉइड रोग को रोकने के लिए सुझाव थायरॉइड रोग को रोकने के लिए कुछ सुझाव हैं। इनमें विभिन्न जीवनशैली कारकों और व्यवहारों को अपनाना शामिल है, जैसेः

पर्याप्त आयोडीन, सेलेनियम और लौह सेवन के साथ स्वस्थ आहार बनाए रखना

धूम्रपान से बचें

अत्यधिक शराब के सेवन से परहेज़ करना

प्रबंधन तनाव

पर्याप्त नींद लेना, और

विटामिन डी के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए सुरक्षित धूप में रहना।

इसके अतिरिक्त, किसी भी संभावित थायरॉयड विकार का शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए नियमित जांच और थायरॉयड कार्य की निगरानी महत्वपूर्ण है।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में CM रेखा गुप्ता ने पेश किया 'विकसित दिल्ली' का रोडमैप

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति आयोग की बैठक में विकसित दिल्ली का रोडमैप पेश किया। 2047 तक दिल्ली को स्वच्छ और सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा। CM ने बताया कि दिल्ली में यमुना की सफाई बुनियादी ढांचे का विकास और हर घर में नल से जल सरकार की प्राथमिकता है।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'विकसित दिल्ली' का रोडमैप प्रस्तुत किया।

कहा, प्रधानमंत्री और नीति आयोग के सहयोग से वर्ष 2047 तक दिल्ली को स्वच्छ, समावेशी और सशक्त बनाने के साथ ही इसे विश्व का श्रेष्ठतम शहर बनाया जाएगा।

यमुना की सफाई, आधारभूत ढांचे का विकास और हर घर नल से जल सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के लोगों को बेहतर सुविधाएं देना सरकार का दायित्व है। दिल्ली में हर राज्य का दिवस उत्सव मनाया जा रहा है।

स्कोप, स्केल, स्पीड और स्किल के साथ होगा दिल्ली का विकास

उन्होंने कहा, दिल्ली के समग्र विकास के लिए उत्कृष्ट आधारभूत ढांचा विकसित करने को चार एस (स्कोप, स्केल, स्पीड और स्कील) के सिद्धांत पर आधारित रणनीति तैयार की गई है।

निर्बाध कनेक्टिविटी और स्मार्ट निगरानी के माध्यम से दिल्ली एक नई पहचान स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रदूषण मुक्त दिल्ली अगली प्राथमिकता है।

सार्वजनिक परिवहन को 100% इलेक्ट्रिक मोड में लाया जाएगा

इसके लिए सार्वजनिक परिवहन को 100% इलेक्ट्रिक मोड पर लाने का लक्ष्य है। इस परिवर्तन की शुरुआत देवी बस सेवा से की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष में 2000 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2047 तक दिल्ली को बनाना है शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत दिल्ली ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई 78,000 रुपये /प्रति तीन किलोवाट सब्सिडी के साथ ही 30,000 रुपये प्रति उपभोक्ता की अतिरिक्त राशि अपनी ओर से टाप-अप के रूप में दी जा रही है।

सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। राजधानी के तीनों कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण का कार्य भी केंद्र सरकार के सहयोग से तेज़ी से जारी है। वर्ष 2047 तक दिल्ली को

शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है।

नए अस्पतालों के निर्माण की विस्तृत योजना की गई तैयार

राजधानी में किसी भी नागरिक की समय पर उपचार के अभाव में मौत न हो इसके लिए आयुष्मान भारत, वय वंदना योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जैसी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को अतिरिक्त समर्थन देकर लागू किया है।

नए अस्पतालों के निर्माण की विस्तृत योजना भी तैयार की गई है। हर घर नल से जल सुनिश्चित करने के लिए समग्र और चरणबद्ध योजना तैयार की है।

यमुना नदी का पुनर्जीवन और जल संरक्षण है सरकार की प्राथमिकता

नए जल शोधन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। यमुना नदी का पुनर्जीवन और जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन जैसी योजना प्राथमिकता में शामिल हैं।

यमुना में गंदा पानी न गिरे इसके लिए 40 नए विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्र (डीएसटीपी) स्थापित होंगे। यमुना की सफाई व राजधानी के विकास के लिए केंद्र के साथ ही पड़ोस के राज्य हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश से ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है।

निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए लाया जाएगा विधेयक

उन्होंने कहा, फीस वृद्धि में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और पारदर्शिता विनियमन) विधेयक, 2025 लाया जा रहा है।

अब दिल्ली के छात्र भी केंद्र सरकार की पीएम श्री स्कूल योजना का लाभ उठा सकेंगे। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में पहली बार इनवेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। इससे निवेश के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

बवाना में फैक्ट्री में भीषण आग, विस्फोट के बाद इमारत ढह गई

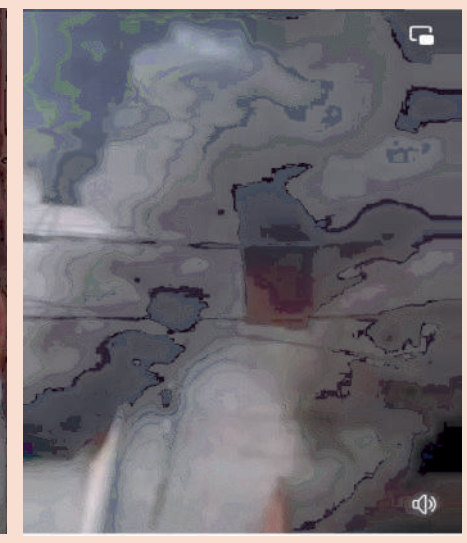

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के बवाना में DSIDC औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 2 के J-10 में स्थित एक फैक्ट्री में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना सुबह करीब 4:48 बजे मिली, जो D.BWN फायर स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती है। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार, आग पर काबू पाने के लिए कुल 17 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग की तीव्रता काफी अधिक थी और परिसर के अंदर हुए विस्फोट के कारण फैक्ट्री की इमारत आंशिक रूप से ढह गई। फिलहाल, किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बची हुई लपटों को बुझाने और संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दमकलकर्मी मौके पर मौजूद हैं। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और आगे की जांच जारी है।

दिल्ली में बिजली की मांग जाएगी 9000 मेगावाट पार, रावतभाटा के परमाणु ऊर्जा संयंत्र से पूरी की जा रही मांग

दिल्ली में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और इस बार 9000 मेगावाट पार करने की आशंका है। डिस्कॉम इस मांग को पूरा करने के लिए रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली ले रहा है। डीईआरसी ने विभिन्न डिस्कॉम को इस बिजली का आवंटन करना शुरू कर दिया है।

नई दिल्लीः दिल्ली में बिजली की मांग में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है। इस बार नौ हजार मेगावाट के पार जाने की संभावना है। इसे पूरा करने के लिए बिजली वितरण कंपनियां (डिस्काम) देशभर में स्थित अलग-अलग संयंत्रों से बिजली खरीद रही है। ऐसे में इस बार राजस्थान के रावतभाटा स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र से भी दिल्ली की मांग को पूरा करने में मदद मिल रही है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र से दिल्ली को 101.11 मेगावाट बिजली मिली

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को पिछले वर्ष भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड की ओर से रावतभाटा स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र से दिल्ली को 101.11 मेगावाट बिजली देने की जानकारी दी गई थी।

आयोग ने पिछले पांच वर्षों में इस संयंत्र से मिलने वाली बिजली में से टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को 32.43 , बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड को 44.71, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड को 23.20 और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज को 0.77 मेगावाट बिजली आवंटित की है।

पिछले माह से आपूर्ति भी शुरू हो गई है। जानकारी अनुसार 25 से 30 मेगावाट बिजली मिल रही है। शीघ्र ही आवंटन के हिसाब से आपूर्ति होगी।

पिछले वर्ष 19 जून बिजली की मांग पहुंच गई थी 8656 मेगावाट

डिस्काम अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 19 जून अधिकतम बिजली की मांग 8656 मेगावाट पहुंच गई थी। इस बार 7748 मेगावाट तक मांग पहुंच गई। आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है।

डिस्काम मांग पूरा करने के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के साथ ही अन्य राज्यों के बिजली संयंत्रों के साथ दीर्घकालीन व अल्पकालीन समझौते के आधार पर बिजली खरीद रही है।

दिल्ली में अब पेंशन लेने के लिए ये कागज जरूरी, इन लोगों के काटे जाएंगे नाम

दिल्ली सरकार वृद्धावस्था पेंशन लेने वालों के लिए एक नया नियम लागू करने जा रही है। अब हर साल जीवित होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। पेंशन में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार घर-घर जाकर सर्वे कराएगी। अपात्र लोगों को पेंशन से हटाया जाएगा। सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। पेंशन बढ़ने से सरकार पर अतिरिक्त खर्च आएगा।

नई दिल्ली। वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए अब लोगों को हर साल अनिवार्य रूप से लाइफ सर्टिफिकेट यानी जिंदा होने का प्रमाणपत्र देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार इस व्यवस्था को लागू करने जा रही है। पेंशन पाने वालों में गड़बड़ियों की आ रहीं शिकायतों के चलते वृद्धावस्था पेंशन, महिला, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर जल्द ही घर-घर सर्वे होगा।

कोठियों और महंगी कॉलोनियों में रहने वाले पेंशन से हटाए जाएंगे। इस मामले को लेकर सरकार जल्द ही कैबिनेट में फैसला लेने जा रही है। बजट में पेंशन के बढ़े 500 रुपये के लिए सरकार को एक साल में अतिरिक्त 500 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने होंगे। इसमें चार लाख वृद्ध और 1 लाख 35 हजार दिव्यांग शामिल हैं। दिल्ली सरकार इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आ रही है।

भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार चार लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन जारी करती है। यह पेंशन उनकी जीविका का आधार मानी जाती है। मगर सच्चाई यह भी है कि अनेक ऐसे लोग हैं जो इस सरकारी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं जो इसके हकदार नहीं हैं।

वर्षों से यह चला आ रहा है कि बड़ी संख्या में कोठियों और महंगी कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। इसकी कई बार जांच भी हुई है मगर फिर भी तमाम लोग आज भी इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं।

अब सवाल उन जांच पर भी उठ रहा है जो पूर्व में की गई हैं और ऐसे लोगों पर भी सवाल उठ रहा है जो गरीबों का हक मार कर पेंशन सुविधा का लाभ ले रहे हैं।

भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में आने के तीन महीने के अंदर ही इस मामले में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सरकार का मकसद साफ है कि जो सुविधा गरीबों के लिए निर्धारित है उसे अमीर क्यों ले रहे हैं? इसी के तहत अब दिल्ली में पेंशन पा रहे लोगों का फिजिकल वेरीफिकेशन (भौतिक सत्यापन) होगा।

जिससे यह पता चल सके कि क्या वे लोग अपने बताए गए पते पर रह भी रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे पेंशन पाने वाले लोगों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी देना, यानी जिंदा रहने का प्रमाण भी अब अनिवार्य रूप से देना होगा।

अभी तक इसे अनिवार्य नहीं किया गया था। इसी तरह महिला, विधवा, दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन को लेकर ही सख्ती होने जा रही है। सभी मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि सही और जरूरतमंद को ही पेंशन मिल सके।

'फन वे लर्निंग एन.जी.ओ.' द्वारा बच्चों को सिलाई का ज्ञान प्रदान कराते गुरजीत कौर एवं अन्य सहायिका

थिएटर में 'भूल चूक माफ' की स्क्रीनिंग के दौरान देखें जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स की 'परम सुंदरी' का एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक

मुख्य संवाददाता

निर्माता दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स और निर्देशक तुषार जलोटा ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'परम सुंदरी' का एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक जारी कर दिया है, जिसे फिल्म 'भूल चूक माफ' के दौरान सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। इस फिल्म में जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की यह नई रोमांटिक जोड़ी पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही है और ऑन-स्क्रीन इस नई जोड़ी अपनी बेमिसाल रोमांटिक केमिस्ट्री सिनेप्रेमियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पर्दे पर यह नई जोड़ी अनूठा रोमांस करती दिखेगी, जिनके साथ दर्शकों को भी प्यार में पड़ने के लिए तैयार रहना होगा! दरअसल, 'परम सुंदरी' उत्तर-दक्षिण भारत की एक खूबसूरत लवस्टोरी है और इसी के साथ यह अपने दर्शकों को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव देने के लिए तैयार है, जो लुभावना ही नहीं, बल्कि अविस्मरणीय भी होगा। माना जाता है कि पहली फ्रेम ही नहीं, बल्कि हर एंगल से यह नई जोड़ी अपने आकर्षण में दर्शकों को बांधे रखेगी। यही वजह है कि सिनेप्रेमी अभी से इस फिल्म को लेकर कुछ अधिक ही जिज्ञासु नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सोनू निगम की आवाज़ के साथ फिल्म का मधुर बैकग्राउंड स्कोर इसे एक ऐसा म्यूज़िक एलबम बनाता है, जिसे देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि, मैडॉक फिल्म्स बहुत जल्द एक और एलमम भी रिलीज करने वाला है।

कुल मिलाकर, 'परम सुंदरी' सिनेप्रेमियों के दिलों की धड़कनों को तेज करने और पर्दे पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

गर्मियों में कैसे रखें बालों का ख्याल

मुख्य संवाददाता

विटामिन ई युक्त हल्का हेयर ऑयल लगाएं, स्कैल्प को रखें मजबूत और तरोताज़ा

लगातार बढ़ रही गर्मी और उमस में बालों की देखभाल करना चुनौती बन जाता है। ठंडक पाने की कोशिश में हम अक्सर बालों को नज़रअंदाज़ कर बैठते हैं, लेकिन तेज़ धूप, पसीना और बार-बार सिर धोने से बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए हो जाते हैं।

गर्मी में तेल लगाना थोड़ा अटपटा लग सकता है, खासकर जब स्कैल्प पहले से ही चिपचिपा महसूस हो रहा हो, लेकिन बालों को स्वस्थ बनाए रखने का यह एक असरदार तरीका है। मैरिको लिमिटेड की चीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर डॉ. शिल्पा वोरा का मानना है कि यह आम धारणा गलत है कि गर्मी में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए।

गर्मी में स्कैल्प क्यों लगता है चिपचिपा?

गर्मी में स्कैल्प से निकलने वाला पसीना और प्राकृतिक तेल मिलकर सिर की त्वचा को चिपचिपा, खुजली वाला और कई बार बदबूदार बना देते हैं। ऐसे में बहुत से लोग तेल लगाना छोड़ देते हैं, लेकिन यह समाधान नहीं है। इसके बजाय, डॉ. वोरा एक आसान सा रूटीन अपनाने की सलाह देती हैं जो बालों को जड़ों से सिरों तक पोषण देता है।

एक सिंपल रूटीन अपनाएं

हफ्ते में एक या दो बार हल्का तेल ज़रूर लगाएं। स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें ताकि रक्त संचार बेहतर हो। फिर बालों की लंबाई में नीचे तक तेल लगाएं। करीब 30 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें। इससे बालों में नमी बनी रहती है और वे चिपचिपे भी नहीं लगते।

मौसम के अनुसार चुनें सही तेल

गर्मियों में ऐसा तेल चुनें जो हल्का हो, चिपचिपा न लगे, जल्दी अवशोषित हो जाए और जिसकी खुशबू ताज़गी दे। डॉ. वोरा ऐसे तेल की सलाह देती हैं जिसमें नारियल तेल, विटामिन ई और जैस्मिन एक्सट्रैक्ट मौजूद हों। ये बालों को गहराई से पोषण देते हैं, नमी बनाए रखते हैं और बालों को मुलायम, मज़बूत व चमकदार बनाते हैं।

अगर आप एक ऐसा रेडी-टू-यूज़ तेल ढूंढ रहे हैं जो इन सभी खूबियों के साथ आए, तो पैराशूट एडवांस्ड जैस्मिन हेयर ऑयल बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह बालों को बिना चिपचिपाहट के पोषण देता है, उनकी चमक बढ़ाता है और इसकी सौम्य खुशबू हर बार सिर में लगाने पर एक मिनी-स्पा जैसा अनुभव देती है। इससे की गई हल्की मसाज से सिर तरोताज़ा महसूस करता है और बाल गर्मी के लिए तैयार हो जाते हैं।

बस थोड़ा ध्यान, सही तेल और आसान साप्ताहिक रूटीन अपनाकर आप पूरे मौसम अपने बालों को स्वस्थ, चमकदार और खूबसूरत बनाए रख सकते हैं।

राम मंदिर का जून में पूरा होगा निर्माण,इस दिन होगी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा,जानें पूरी डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

अयोध्या। राम मंदिर परिसर में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार के मूर्ति की प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है,यहां गर्भगृह से लेकर सभी मंडपों के फर्श तक का सभी काम पूरा हो गया है।राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख भी आ गई है।

श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि अयोध्या में प्रतिष्ठित राम मंदिर का निर्माण 5 जून तक पूरा हो जाएगा और तीन जून से शुरू होने वाले समारोह में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मिश्रा ने बुधवार को कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह पांच जून को होगा और इसके बेहद भव्य होने की उम्मीद है, लेकिन इस बार अतिथियों की लिस्ट भिन्न हो सकती है।

नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि पिछले साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में एक समारोह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मिश्रा ने कहा कि राम दरबार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को होगी। अनुष्ठान तीन जून से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा परिसर में सात अन्य मंदिर भी बनाए गए हैं और उन मंदिरों के लिए भी धार्मिक अनुष्ठान उसी दिन किए जाएंगे।मिश्रा ने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य पांच जून तक पूरा हो जाएगा, सिवाय भगवान राम की कहानी को दर्शाने वाले भित्ति चित्रों के,जिन्हें मंदिर के निचले हिस्से में लगाया जाना है।

नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट अंतिम रूपरेखा तय कर रहा है।प्राण प्रतिष्ठा समारोह हमेशा भव्य होते हैं। क्योंकि आप स्पष्ट रूप से आह्वान कर रहे हैं और भगवान की प्रतिष्ठा की जा रही है,लेकिन शायद गेस्ट की लिस्ट अलग होगी, हो सकता है कि पूजा कराने वाले पुजारी अलग हों,इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि यह उसी के समान है,लेकिन मैं कहूंगा कि इसका उद्देश्य वही है और यह उसे हासिल करेगा।

नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि गेस्ट लिस्ट में राज्य या केंद्र के विशिष्ट लोग शामिल नहीं होंगे।ट्रस्ट इस पर विचार कर रहा है और शायद वे उस समारोह के समय विभिन्न धर्मों के कई आध्यात्मिक गुरुओं को भी आमंत्रित करेंगे। मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य या केंद्र सरकार से किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

नृपेंद्र मिश्रा ने इस बात से इनकार किया कि मंदिर निर्माण के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य था।मुझे नहीं लगता कि यह कोई राजनीतिक नौटंकी है या इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है। यह हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है और यह क्षण 500 वर्षों से अधिक संघर्ष के बाद आया है। मिश्रा ने कहा कि 5 जून के समारोह के एक हफ्ते के भीतर मंदिर के नए हिस्से को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाने की उम्मीद है।

विधायक का विधानसभा पास चोरी करने में कानपुर में तीन को भेजा जेल

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी का विधान सभा पास चोरी करने के आरोप में पुलिस नेसर्विस सेंटर के कर्मचारी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इनके पास से चुराया गया विधानसभा का पास भी बरामद हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उन्होंने सुरेंद्र मैथानी का विधानसभा का पास यह पास

टोल टैक्स बचाने को और रास्ते में पुलिस और लोगों पर धाक जमाने के लिए चोरी किया गया था।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के ड्राइवर ने ही फॉर्चुनर कार वाले अपने दोस्त के लिए यह पास चुराया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को सीसीटीवी की जांच से निकले नतीजे के आधार पर गिरफ्तार किया।

अवगत कराते चलें कि गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अपनी फॉर्चुनर कार सनी टोयोटा सर्विस सेंटर एनएच-2 रूम और क्षेत्र कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर सर्विस के लिए 17 मई को दिया था। 21 मई की शाम को विधायक ने सर्विस के बाद अपनी कार को वहां से रिसीव किया तो उसमें लगा हुआ विधानसभा का पास गायब था। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने महाराजपुर थाने में दर्ज कराई थी।

महाराजपुर थाना प्रभारी संजय पांडेय ने जांच शुरू की तो सामने आया कि सर्विस सेंटर में ड्राइवर की नौकरी करने वाले कोहना निवासी अमित मिश्रा ने पास चोरी किया था।

पास चोरी करने के बाद रावतपुर निवासी मेडिकल स्टोर संचालक लकी सैनी को बेचा था। इसमें लकी सैनी का दोस्त लक्ष्य चतर्वेदी भी शामिल था। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखा दिया है।

132 हिरण के लिए नोएडा में बनेगा अनोखा डियर पार्क, 40 करोड़ होंगे खर्च

नोएडा के सेक्टर-91 बायोडायवर्सिटी पार्क में डियर पार्क और सनसेट सफारी बनने जा रही है। इसके लिए दो वन्यजीव सलाहकारों की नियुक्ति हुई है। यहाँ नोएडा एयरपोर्ट से रेस्क्यू किए हिरणों के साथ अन्य चिड़ियाघरों से हिरण लाए जाएंगे। इस डियर पार्क को बनाने में लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसमे स्पेक्ट्रम लाइट की मदद से रात में भी हिरणों को देखा जा सकेगा।

नोएडा। सेक्टर-91 बायोडायवर्सिटी पार्क में प्रस्तावित डियर पार्क सनसेट सफारी के लिए दो सलाहकार को नियुक्त किया गया है। इसमें एक रिटायर्ड आईएफएस प्रवीन चंद त्यागी और दूसरे संजय श्रीवास्तव है। दोनों अधिकारियों का वाइल्ड लाइफ में गहरा अनुभव रहा है। प्राधिकरण ने बताया कि दोनों अधिकारियों की गाइडेंस में ही डियर पार्क का सेटअप किया जाएगा।

एक आर्किटेक्ट को भी नियुक्त किया जाएगा। यह सलाहकार के कहने पर ही केज डिजाइन, बाड़ा और अन्य प्रकार की टेक्निकल काम का डिजाइन बनाएगा। बता दें कि यहां नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से रेस्क्यू किए जाने वाले हिरण को भी रखा जाएगा।

हालांकि उनके लिए धनौरी वेटलैंड के पास से रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जा रहा है। वहां से कुछ हिरण को यहां भी लाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के अन्य चिड़ियाघरों से भी हिरण को यहां लाया जाएगा। करीब 30 एकड़ में मिनी जू की तर्ज पर इस डियर पार्क को बनाने में करीब 40 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

यह जिले की पहली सनसेट सफरी होगी। इसमें रात करीब 10 बजे तक लोग स्पेक्ट्रम लाइट की रोशनी में हिरण व जलीय पक्षियों को देख सकेंगे। स्पेक्ट्रम लाइट में वहां पर मौजूद जानवरों को अंधेरा ही लगेगा। वहीं जो लोग सनसेट सफरी में पहुंचेंगे उनको स्पष्ट दिखाई देगा।

नोएडा में 10 प्रजातियों के 132 हिरण को लाया जाएगा। इसमें तीन प्रजाती अफ्रीका से एक्सपोर्ट की जाएंगी। इसक अलावा कानपुर, हैदराबाद और लखनऊ के चिड़ियाघर से यहां हिरण लाए जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि नोएडा, गाजियाबाद और आसपास में ऐसा डियर पार्क नहीं है।

इसलिए यहां डियर पार्क बनाया जा रहा है। इसके लिए नियुक्त किए गए सलाहकारों से बातचीत की जा रही है। ताकि विदेश से लाए जाने वाले हिरण के लिए यहां का पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। प्राधिकरण अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने बताया कि एक बार डिजाइन बनने के बाद सिविल कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जुलाई तक टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने की उम्मीद है। निर्माण पूरा होने के बाद ही हिरण को यहां लाया जाएगा। यहां नाइट सफारी भी रहेगी। ऐसे में सलाहकार के डायरेक्शन के बाद ही तय होगा कि डियर के लिए यह कितना अनुकूल है। साथ ही यहां और कौन कौन से जंतु लाए जा सकते है।

गंगा दशहरा को लेकर सिविल डिफेंस ने की बैठक

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा: उप नियंत्रक सुमित मौर्य के नेतृत्व मे नागरिक सुरक्षा विभाग मथुरा की वार्डन पोस्ट संख्या एक और क्विक रिस्पांस टीम ने कलेक्ट्रेट स्थित सिविल डिफेंस कार्यालय पर गंगा दशहरा पर्व एवं ईद-उल-जुहा (बकरीद) की तैयारियों को लेकर वार्डन एवं स्वयंसेवक के साथ पोस्ट वार्डन अशोक यादव ने बैठक की जिसमें मन्दिरों के आस-पास सफाई अभियान एवं बाहर से आने वाले यमुना नदी के आस पास के घाटों पर सतर्कता एवं सिविल डिफेंस के वार्डन एवं स्वयंसेवक साथ में गोताखोर टीम लाईफ जैकिट के साथ नजर बनाए रखें साथ ही यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिए कहा गया बही डिविजनल वार्डन भारत भूषण तिवारी पोस्ट वार्डन अशोक यादव के द्वारा वार्डन एवं स्वयंसेवक को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया जिसमें उनको आग से होने बाली घटनाओं को रोकने, सी पी आर, गांठ बांधना एवं एमरजेंसी मैथड के बारे में जानकारी दी गई बैठक में नागरिक सुरक्षा विभाग मथुरा के बड़े बाबू जगदीश सिंह,आलोक व्यास, सेक्टर वार्डन गुलशेर, मुकेश शर्मा, राम सैनी, नरेन्द्र, आदि बैठक में शामिल रहे।

भारत का अतिथि देवो भवः बनाम अमेरिका का अतिथि अपमान भवः

वैश्विक डिजिटल युग में भारतीय संस्कृति संस्कारों व अतिथि देवो भव : जैसे अनेकों परंपराओं संस्कारों का संज्ञान लेकर अनुसरण करना समय की मांग- **एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र**

वैश्विक स्तरपर यह पूरी दुनियाँ जानती है कि भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है, इसीलिए ही भारत की नम्रता एक सिंबाल है अतिथि देवो भवः जो हमने भारत में जी-20 की मेज़बानी में खूब दिखाई, जिससे इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आए करीब 200 देश के सैकड़ो मेहमानों जिसमें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री व प्रतिनिधि तक मेहमान नवाजी से खुश हो गए थे, और हो भी क्यों ना! क्योंकि अतिथि देवो भवः का गुण हमारे राष्ट्रपति पीएम से लेकर अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के हृदय में समाया हुआ है। मेरा मानना है कि निजी स्तरपर शायद इस अतिथि देवो भवः के गुण में हो सकता है कमी आ गई हो परंतु मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि भारतीय शासकीय स्तरपर, विदेशी लीडर्स अफसर, मंत्री प्रतिनिधि जब ऑफीशियली भारत आते हैं तो राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक व उच्चस्तर के अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक भी इस प्रोटोकॉल का पालन करते है, व उस अतिथि को खूब मान सम्मान और उसकी सेवा की जाती है। हालांकि जस्टिस बीआर गवई 14 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद 18 मई को पहली बार महाराष्ट्र गए थे। हालांकि, मुंबई में उन्हें स्टेट चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी या मुंबई पुलिस कमिश्नर में से कोई भी रिसीव करने नहीं आए थे,जिसपर सीज़ेआई गवई ने नाराजगी जाहिर की थी। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। बाद में राज्य के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के प्रदेश ने कहा कि उन्होंने प्रोटोकॉल में चूक के लिए राज्य सरकार की ओर से सीज़े आई गवई से फोन पर माफी मांगी है। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरुवार दिनांक 22 मई 2025 को देर शाम साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में ऑफिशियल मीटिंग के समय तनातनी तीखी नोक झोक की किलिप्स सोशल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया पर जोरदार ढंग से वायरल हो रही है। ठीक वैसा ही व्यवहार व्हाइट हाउस में बीते दिनों फ़रवरी 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी ऑफिशियल बातचीत तीखी बहस के रूप में परिवर्तित हो गई थी, इसके पूर्व 2017 में भी व्हाइट हाउस में ट्रंप व मर्केल के बीच मुलाकात के दौरान कैमरे के सामने ट्रंप नें हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। मेरा मानना है कि यह अतिथि का अपमान है क्योंकि किसी को भी हम अपने शासकीय या निजी स्थान पर ऑफीशियली आमंत्रित करते हैं, न्योता देते हैं तो उसका मान सम्मान करना न केवल हमारा मानवीय धर्म है बल्कि प्रोटोकॉल भी है। चूँकि भारत का अतिथि देवो भवः बनाम अमेरिका का अतिथि अपमान भावः तथा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क़े बाद अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफ़ोसा से ट्रंप की ऑन कैमरा नोक झोक क्या अपमान नहीं ?इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, विश्व के डिजिटल युग में भारतीय संस्कार संस्कृति व अतिथि देवो भवःजैसी अनेकों परंपराओं का संज्ञान लेकर अनुसरण करना आज समय की मांग है ?

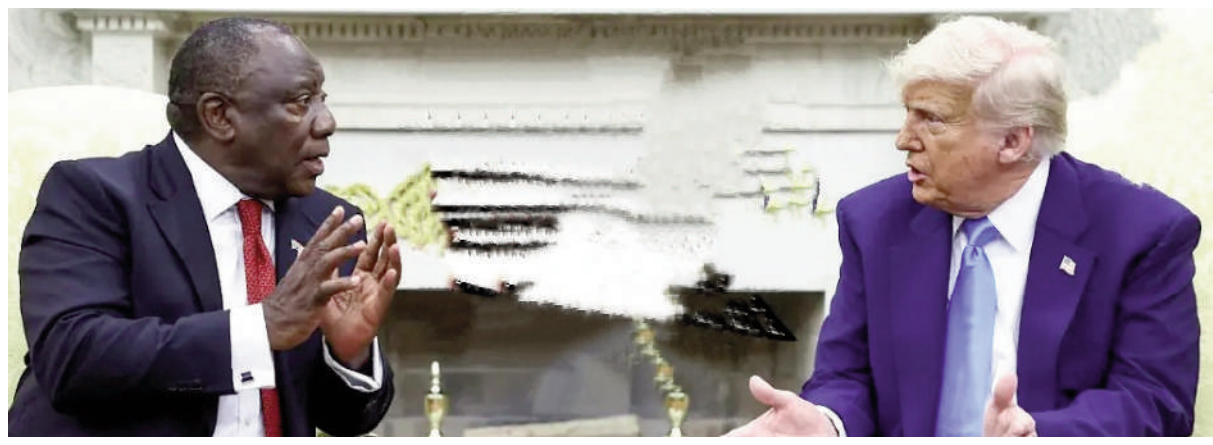

साथियों बात अगर दिनांक 22 मई 2025 को देर शाम व्हाइट हाउस में रामाफोसा व ट्रंप के बीच ऑन कैमरा तथा कथित तनातनी व अपमान की करें तो,बुधवार को डॉनल्ड ट्रंप के बुलावे पर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा अमेरिका दौरे पर पहुंचे थे, ये दौरा मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर था, लेकिन मीटिंग के दौरान एक पत्रकार ने दक्षिण अफ्रीका में कथित श्वेत नरसंहार को लेकर मुद्दा उठा दिया, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने इसके बाद जो किया उसने सभी को चौंका दिया, उन्होंने ओवल ऑफिस की लाइटें बंद करवा दी, ट्रंप दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति को दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों के खिलाफ हुए कथित आंदोलन के वीडियोज दिखाने लगे, डोनल्ड ट्रंप ने पहले से ही सारे वीडियोज को एडिट करवा के रखा था,यानें सिरिल रामफोसा को अपमानित करने की उनकी मंशा साफ-साफ दिख रही थी। ट्रंप यहीं नहीं रुके, वापस जब लाइटें ऑन हुईं तो ट्रंप कई अखबारों के आर्टिकल लेकर बैठे थे, जिसमें अश्वेत लोगों की मौत की खबरें थीं, ट्रंप एक एक कर के सारे आर्टिकल दिखाने लगे। बीते 10-15 मिनट से एक के बाद एक, आरोपों के बाण झेल रहे दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था, उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि वो यहां आने के अपने फैसले पर पछता रहे थे, लेकिन ट्रंप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो सवाल पर सवाल दागते जा रहे थे,आखिरकार दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने बड़ी ही विनम्रता के साथ उन्हें पूरा मामला समझाया और इन आरोपों का जवाब भी दिया।ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने घर बुलाकर किसी अंतरराष्ट्रीय नेता को बेइज्जत किया है, इससे पहले फरवरी के महीने में भी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने अपने मेहमान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पूरी दुनियाँ के सामने बेइज्जत किया था।तीन साल से रूस से जंग लड़ रहे जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति से मदद मांगने आए थे, लेकिन यहां उन्हें फटकार लगा दी गई, तब राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वांस दोनों एक साथ जेलेंस्की पर टूट पड़े थे। ट्रंप ने दावा किया की द.अफ्रीका में श्वेत किसानों का कत्ल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका में रेसिज्म यानी रंगभेद का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन श्वेत किसानों के नरसंहार का जो दावा ट्रंप कर रहे हैं,दक्षिण अफ्रीका के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि वहां औसतन हर साल 27000 मर्डर रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनमें से श्वेत किसानों की हत्या के सिर्फ 1 पेर्सेंट मामले हैं, एक और आंकड़ा बताता है कि अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच वहां 6,953 हत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से श्वेत किसान की हत्या का सिर्फ 1 मामला है। मानवाधिकार संस्थाएं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी माना कि किसानों की हत्या तो हो रही है लेकिन इसमें नस्लीय हिंसा का कोई एंगल नहीं है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप ने ये मुद्दा उठाया क्यों? इस मुद्दे के बहाने अपने मेहमान को ओवल ऑफिस में मीडिया के सामने बेइज्जत किया क्यों, अमेरिका की राजनीति में भी श्वेत-अश्वेत का मामला काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है, ऐसे में ये नैरेटिव ट्रंप के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप ने अपने राजनीतिक हित के लिए सिरिल रमाफोसा को बेइज्जत किया, लेकिन यहां डॉनल्ड ट्रंप ने जो किया उसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की, डॉनल्ड ट्रंप अपने मेहमान से ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगे जिससे वो असहज हो गए. ऐसा लग रहा था जैसे ट्रंप दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति का वेलकम करने नहीं बल्कि बेइज्जत करने की तैयारी के साथ आए हों। हमारे मन में अतिथि के लिए कभी भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए और हमें कभी उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कभी भी अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता भगवान भी उसके घर नहीं आते है। यदि आप अतिथि का सम्मान नहीं करते तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। अतिथि पूजनीय है और उनका आगमन जीवन में खुशियाँ भर जाता है।

साथियों बात अगर हम भारत के अतिथि देवो भवः संस्कारों की करें तो, अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उनसे चाय-नाश्ता पूछते हैं, मेहमानों के आते ही बच्चों को गरमा-गरम समोसा, रसगुल्ले और कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए भेजते हैं, ये हमारी संस्कृति है. जहां मेहमान को भगवान माना जाता है, अतिथि देवो भवः के संस्कार हैं, हमारे यहां तो बिनबुलाए मेहमान को भी बहुत इज्जत दी जाती है, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे शख्स की मेहमाननवाजी दिखाते हैं, डॉनल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपित सिरिल रामफोसा को अपने घर यानी व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया, व्हाइट हाउस की परंपरा के मुताबिक ओवल ऑफिस में दोनों के बीच द्वीपक्षीय वार्ता हुई,वहां दुनियाँ भर के अधिक बहुत पत्रकार जमा हुए।

साथियों बात अगर हम रामाफोसा व ट्रंप की मीटिंग में रिपोर्टरों के प्रश्नों क़े दोनों नेताओं के उत्तर की करें तो एक रिपोर्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कतर से मिले 400 मिलियन डॉलर के विमान को स्वीकार करने पर सवाल किया। रिपोर्टर ने इतना महंगे उपहार स्वीकार करने में नैतिकता आड़े आने की बात कही तो ट्रंप गुस्सा हो गए। उन्होंने रिपोर्टर को बेशर्म कहते हुए इस तरह के सवाल ना करने को कहा। इस पर रामफोसा ने हंसते हुए कहा कि मेरे पास तो ट्रंप को देने के लिए को महंगा विमान नहीं है। ट्रंप ने इस पर कहा कि अगर आपका देश यूएस एयर फोर्स को एक विमान देता तो मैं इसे जरूर स्वीकार कर लेता। रामफोसा ने ट्रंप के आरोपों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आप सच्चाई नहीं जानते हैं। रामाफोसा ने शांति से कहा, 'ये सही है कि साउथ अफ्रीका में अपराध है लेकिन इसके ज्यादातर शिकार अश्वेत हैं।' इस पर ट्रंप ने उनको बीच में टोकते हुए कहा कि टारगेट किलिंग का शिकार किसान अश्वेत नहीं हैं। इससे माहौल में भारी तनाव पैदा हो गया।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत का अतिथि देवो भवः बनाम अमेरिका का अतिथि अपमान भवःयूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफ़ोसा से ट्रंप की ऑन कैमरा नोक झोक क्या अपमान नहीं ?वैश्विक डिजिटल युग में भारतीय संस्कृति संस्कारों व अतिथि देवो भवःजैसे अनेकों परंपराओं संस्कारों का संज्ञान लेकर अनुसरण करना समय की मांग।

1 जुलाई को हीरो लॉन्च करेगी दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत होगी बहुत कम

परिवहन विशेष न्यूज

हीरो मोटोकॉर्प 1 जुलाई 2025 को Vida ब्रांड के तहत दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी। कंपनी का लक्ष्य किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करना है जो नए ACPD प्लेटफॉर्म पर बनेंगे और पेट्रोल स्कूटरों की कीमत के करीब होंगे। वर्तमान में Vida के तीन वेरिएंट उपलब्ध हैं जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 74000 रुपये से 1.15 लाख रुपये तक है। नए मॉडल और भी सस्ते हो सकते हैं।

नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार में 1 जुलाई 2025 को अपने दो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है। कंपनी इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को Vida ब्रांड के तहत लॉन्च करेगी। कंपनी ने इसके बारे में वित्तीय वर्ष 2025 की मीटिंग के दौरान दी। आइए जानते हैं कि Vida के ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को किन बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा और इनकी कीमत कितनी हो सकती है?

नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या होगा खास?

हीरो मोटोकॉर्प का प्लान है कि वह सस्ते और ज्यादा लोगों की पहुंच में आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आएं। इन नए स्कूटरों को नए प्लेटफॉर्म (ACPD) पर बनाया जा रहा है। जिसकी वजह से इसकी कीमत पेट्रोल वाले स्कूटरों के करीब हो सकती है। हाल में इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida को तीन वेरिएंट में भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है, जो V2 Lite, V2 Plus और V2 Pro है। यह तीनों ही कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है।

कितनी होगी कीमत?

मौजूदा Vida स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 74,000 रुपये से लेकर 1.15 लाख रुपये है। हीरो के आने वाले नए स्कूटर इससे भी सस्ते हो सकते हैं, जिनकी मदद से कंपनी ज्यादा लोगों तक पहुंच बना सकती है। हाल के समय में कंपनी हर महीने करीब 7,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है। नए स्कूटरों के लॉन्च होने के बाद यह प्रोडक्शन संख्या 15,000 यूनिट प्रति माह तक पहुंच सकती है। नए इलेक्ट्रिक स्कूटरों बिक्री के लिए कंपनी देशभर में अपनी Vida डीलरशिप बढ़ा रही है। हाल के समय में Vida के पास 203 टचपॉइंट्स हैं, जिनमें से 180 डीलरशिप 116 शहरों में है।

Hero इलेक्ट्रिक स्कूटर के बिक्री का हाल

वित्तीय वर्ष 2025 में Hero ने 48,673 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री की है, जो पिछले साल की तुलना में 175% ज्यादा की बढ़ोतरी है। पिछसे साल FY2024 में हीरो की 17,720 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री हुई थी। भारतीय बाजार में Vida का मुकाबला Ola Electric, Ather, Bajaj, TVS और Ampere जैसी कंपनियों से होती है।

लॉन्च से पहले जानिए वोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई के 5 बेहतरीन फीचर्स, जिनकी वजह से पहली खेप हुई पूरी बुक

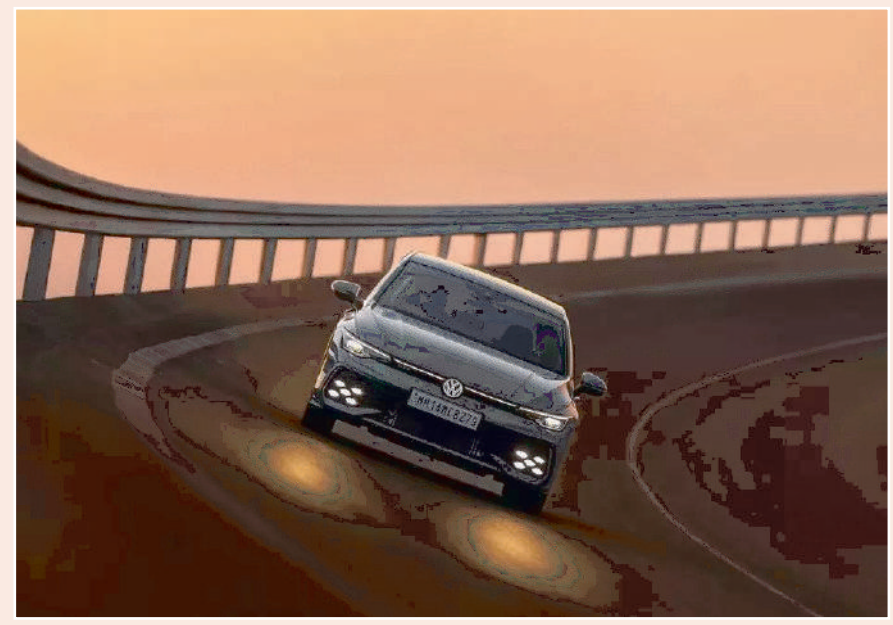

परिवहन विशेष न्यूज

वोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई भारत में 26 मई 2025 को लॉन्च होगी। इसमें 2.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 265hp की पावर देता है। यह 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है। स्पोर्टी लुक और शानदार फीचर्स इसे खास बनाते हैं। इसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये से 55 लाख रुपये के बीच होगी। पहली खेप की सभी 150 यूनिट बिक चुकी हैं।

नई दिल्ली। Volkswagen Golf GTI भारत में 26 मई, 2025 को लॉन्च होने वाली है। यह कंपनी की पॉपुलर और पावरफुल हैचबैक कार है। इसे दुनियाभर में बेहतरीन परफॉर्मेंस और शानदार स्टाइल के लिए जानी जाती है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको इसके ऐसे शानदार 5 फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, जो इसे बाकियों से काफी अलग बनाते हैं?

1. दमदार इंजन और तेज स्पीड

इसमें 2.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 265hp की पावर और 370Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (DCT) और पैडल शिफ्टर्स के साथ ऑफर किया जाएगा। यह 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 267 किमी/घंटा है।

2. स्पोर्टी लुक

Volkswagen Golf GTI का डिजाइन काफी स्टाइलिश और स्पोर्टी है। इसमें रेड लाइन वाली ग्रिल, GTI बैज, हनीकॉम्ब डिजाइन वाला बंपर और डुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, जो इसके लुक को दमदार बनाते हैं। इसे भारत में Moonstone Grey, Kings Red, Onyx White, और Grenadilla Black में लाया जा रहा है।

3. फीचर्स से भरपूर इंटीरियर

इसमें Tartan डिजाइन वाले स्पोर्ट्स सीट्स दी गई है, जिनपर रेड कलर में GTI का लोगो दिया गया है। इसमें 12.9 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल डिस्प्ले, सिंगल पेन सनरूफ, तीन ज़ोन AC, ADAS सुरक्षा फीचर, और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स मिलेंगे।

4. कितनी होगी कीमत?

Volkswagen Golf GTI को भारत में 50 लाख रुपये से 55 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत के बीच लॉन्च किया जा सकता है। यह पूरी तरह से इम्पोर्टेड होगी यानी विदेश से पूरी बनी हुई कार भारत लाई जाएगी। भारत में इसका मुकाबला Mini Cooper S से देखने के लिए मिलेगा।

5. पहली खेप की सभी कारें बिक चुकी

कंपनी ने भारत के लिए इसकी पहली खेप में केवल 150 यूनिट को ही मंगवाया था, जिनकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि दूसरी खेप में 100 और यूनिट्स लाई जाएंगी, जिनकी डिलीवरी अगले साल से शुरू की जाएगी।

कावासाकी की इस पावरफुल बाइक पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर, कई एडवांस फीचर्स से है लैस

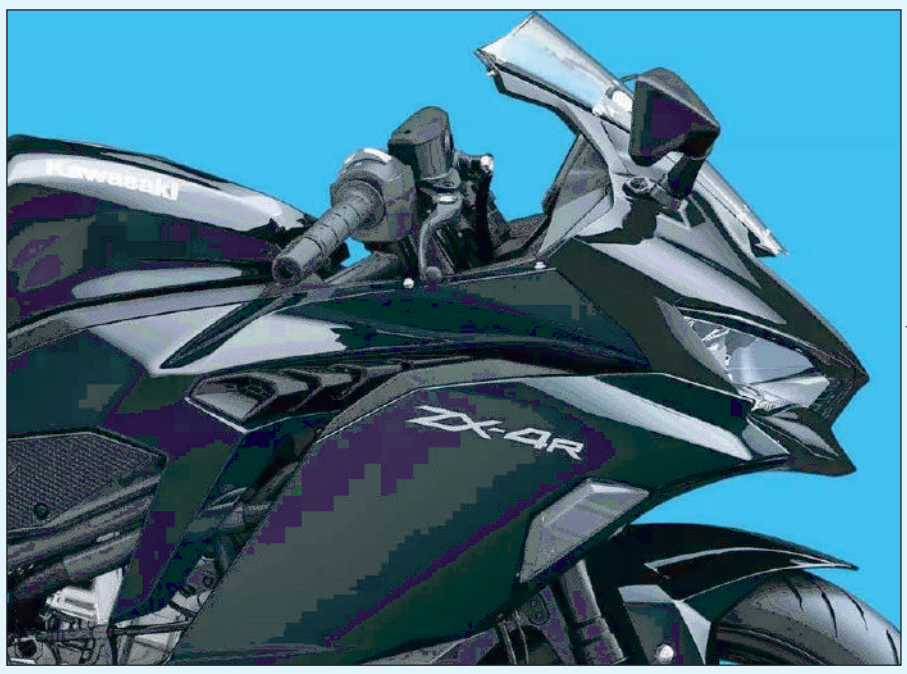

कावासाकी मई 2025 में निंजा ZX-4R स्पोर्ट्स बाइक पर 40 हजार रुपये का डिस्काउंट दे रही है जिससे एक्स-शोरूम कीमत 8.39 लाख रुपये हो गई है। इस बाइक में 399cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 77 hp की पावर और 39 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है और इसमें कई राइडिंग मोड्स और 4.3-इंच की TFT स्क्रीन जैसे फीचर्स हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। कावासाकी मई 2025 में अपनी स्पोर्ट्स बाइक Kawasaki Ninja ZX-4R पर जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है। इस छूट के बाद बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 8.39 लाख रुपये हो गई है, जबकि इसकी पहले एक्स-शोरूम कीमत 8.79 लाख थी। कंपनी इस बाइक पर 40 हजार रुपये का डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट का फायदा मई के आखिरी तक मिलेगा। आइए जानते हैं कि इस कावासाकी की बाइक किन बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है।

पावरफुल इंजन

Kawasaki Ninja ZX-4R में 399cc का लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गयाय है, जो 77 hp की पावर 39 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह कंपनी की सबसे किफायती इनलाइन-फोर स्पोर्ट्स बाइक में से एक है।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम

Ninja ZX-4R में ट्रेलिस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। इसके सामने की तरफ 37mm यूएसडी फोर्क और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जिसमें प्रीलोड एडजस्टमेंट मिलता है। इसमें ब्रेकिंग के लिए आगे 290mm ड्यूल डिस्क और पीछे 220mm सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया है। वहीं, आगे का टायर 120/70-ZR17 और पीछे का टायर 160/60-ZR17 साइज का मिलता है, जो बाइक की सड़क पर पकड़ को बनाए रखता है।

फीचर्स

Ninja ZX-4R में 4.3-इंच की TFT स्क्रीन दी गई है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें चार राइडिंग मोड मिलता है, जो Sport, Road, Rain और Rider है। इसके अलावा, इस बाइक में फुल एलईडी लाइट्स, जिसमें ZX-10R जैसे टेललाइट्स के साथ ही डुअल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड भी दिया गया है।

किन मोटरसाइकिल से मुकाबला?

मई 2025 में छूट के बाद Kawasaki Ninja ZX-4R की एक्स-शोरूम कीमत 8.39 लाख रुपये हो गई है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Honda CBR650R, Triumph Daytona 660, और Suzuki GSX-8R जैसी स्पोर्ट्स बाइक से होता है।

केंद्र सरकार ला सकती है नई टोल पॉलिसी, 3000 रुपये का पास और सालभर टोल की टेंशन खत्म

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार FASTag सिस्टम में बदलाव करने जा रही है। नई नीति के तहत वाहन मालिक 3000 रुपये का वार्षिक भुगतान करके पूरे साल नेशनल हाईवे पर सफर कर सकेंगे। इसके अलावा कम सफर करने वालों के लिए प्रति 100 किलोमीटर का 50 रुपये का भुगतान करने का विकल्प भी होगा। इस सिस्टम से टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और फ्यूल की भी बचत होगी।

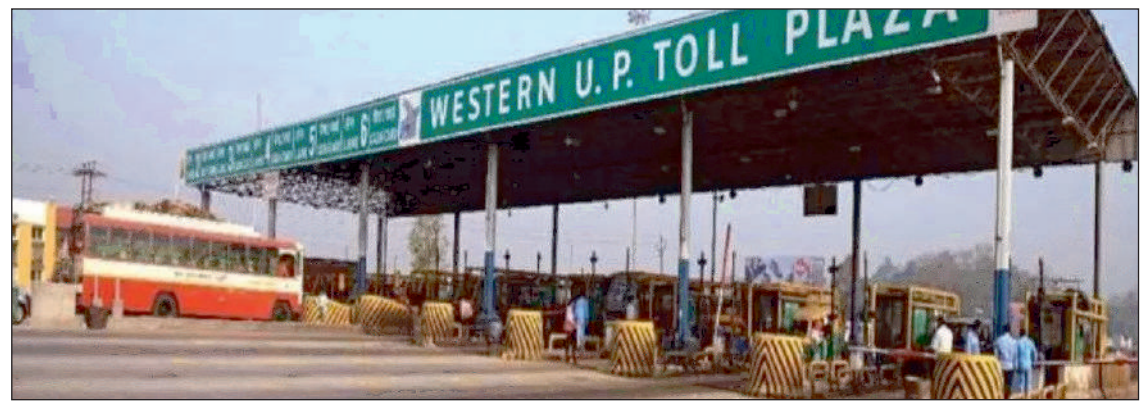

नई दिल्ली। भारत सरकार ने हाल ही में FASTag सिस्टम में कुछ जरूरी बदलावों की घोषणा की है। इसके जरिए टोल कलेक्शन को ज्यादा सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना है। इस नए सिस्टम के आने के बाद लोगों को टोल का भुगतान करने में आसानी होगी और सफर पहले से बेहतर हो जाएगा। आइए जानते हैं कि FASTag सिस्टम को लेकर क्या बदलाव हो सकते हैं और इसका लोगों को क्या फायदा मिलेगा?

FASTag सिस्टम में क्या होंगे बदलाव?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई नीति के तहत वाहन मालिक 3000 रुपये का वार्षिक भुगतान करके पूरे साल नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे पर जितनी चाहे उतना सफर कर सकेंगे। यह पास को FASTag अकाउंट से डिजिटल रूप से लिंक होगा, जिसकी वजह से लोगों को बार-बार टोल का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए लोगों को दो पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे, जिसके से एक सालाना पास और दूसरा दूरी-आधारित शुल्क। दूसरा दूरी-आधारित शुल्क उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो कम सफर करते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति 100 किलोमीटर का 50 रुपये का भुगतान करना होगा। नए FASTag सिस्टम में शामिल होने के लिए लोगों को किसी अतिरिक्त कागजात या अकाउंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अपने वर्तमान FASTag खाते का उपयोग करके नई योजना का लाभ उठा सकते हैं।

लोगों को क्या होगा फायदा?

नया FASTag सिस्टम आने के बाद लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और लोगों के फ्यूल की भी बचत होगी। वहीं, नई प्रणाली के तहत टोल प्लाजा पर भौतिक बाधाएं हटा दी जाएंगी, और सेंसर-बेस्ड सिस्टम लागू किया जाएगा। इस नए सिस्टम की मदद से टोल राजस्व की क्षतिपूर्ति और धोखाधड़ी होने वाली चीजों को कम किया जाएगा। वहीं, बैंकों को टोल चोरी रोकने के लिए ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। जल्द ही सरकार इसको लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

होंडा से कावासाकी तक लॉन्च हुई ये शानदार बाइक और स्कूटर, जानिए कैसा बाइक की दुनिया के लिए यह सप्ताह

परिवहन विशेष न्यूज

मई 2025 के तीसरे सप्ताह में होंडा सुजुकी और कावासाकी ने कई नए दोपहिया वाहन लॉन्च किए। होंडा ने CB1000 Hornet SP CB750 Hornet Rebel 500 और X-ADV 750 को पेश किया। सुजुकी ने Avenis स्कूटर का 2025 स्टैंडर्ड वेरिएंट लॉन्च किया जो OBD-2B कंप्लायंट है। कावासाकी ने Versys-X 300 को फिर से भारतीय बाजार में उतारा। KTM RC 200 को नया रंग मिला।

नई दिल्ली। मई 2025 के तीसरे सप्ताह में दोपहिया वाहनों की दुनिया में बहुत कुछ देखने के लिए मिला। इस सप्ताह कुछ नई मोटरसाइकिल लॉन्च हुई, तो कुछ पुराने मॉडल को नए कलर के साथ अपडेट किया है। इसके साथ ही आने वाले महीनों में लॉन्च होने वाली कुछ मोटरसाइकिल और स्कूटर की झलक भी देखने के लिए मिली। आइए जानते हैं कि इस सप्ताह कौन सी बाइक और स्कूटर लॉन्च हुए और किन दोपहिया वाहनों को अपडेट मिला।

1. Honda CB1000 Hornet SP और CB750 Hornet लॉन्च

भारत में Honda CB1000 Hornet SP और CB750 Hornet को लॉन्च कर दिया गया है। CB1000 लॉन्च होने के साथ ही देश की सबसे सस्ती 1000cc की नेकेड बाइक बन गई है। यह दोनों ही दमदार लुक और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आती है। इनमें कई बेहतरीन फीचर्स भी मिलते हैं।

2. Honda Rebel 500 लॉन्च

होंडा टू व्हीलर ने भारतीय बाजार में Honda Rebel 500 को लॉन्च किया। यह एक मॉडर्न क्रूजर मोटरसाइकिल है, जिसमें 471cc का दमदार इंजन मिलता है। इसके साथ ही यह कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है।

3. Honda X-ADV 750 लॉन्च

होंडा टू व्हीलर ने भारत में एडवेंचर स्कूटर Honda X-ADV 750 को लॉन्च किया। यह दुनिया में अपनी तरह की अकेला स्कूटर है। इसमें ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन दिया गया है, जो आमतौर पर कारों में देखने के लिए मिलता है।

4. 2025 Suzuki Avenis Standard Variant लॉन्च

सुजुकी मोटरसाइकिल की पॉपुलर स्कूटर Avenis का नया 2025 Standard वेरिएंट को लॉन्च किया गया है। इसका इंजन अब OBD-2B कंप्लायंट है, जिससे कम प्रदूषण होगा। इसके डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह Avenis का सबसे किफायती स्कूटर है।

5. 2025 Kawasaki Versys-X 300 लॉन्च

कावासाकी ने कई वर्षों के बाद फिर से Kawasaki Versys-X 300 को भारत में लॉन्च किया है। यह एक रोड-बायस्ड एडवेंचर बाइक है। इसमें 296 cc का इंजन दिया गया है और विंडस्क्रीन काफी बेहतरीन दी गई है। इसमें मजबूत बॉडी और आरामदायक सीट दी गई है।

6. 2025 KTM RC 200 को मिला नया रंग

KTM RC 200 को नए कलर Metallic Grey के साथ अपडेट किया गया है। इसे नया कलर ऑप्शन देने के साथ ही इसकी कीमत में 12,000 रुपये तक की बढ़ाया गया है। इस कलर को ब्लैक और ब्लू कलर के बीच रखा गया है।

7. Royal Enfield की नई 250cc की बाइक

Royal Enfield 250cc की मोटरसाइकिल लाने का काम कर रही है। इसके इंजन को चीनी कंपनी CFMoto के साथ मिलकर बनाया जाएगा। इंजन में हाइब्रिड तकनीक होगी, जिससे 55 kmpl तक का माइलेज मिल सकता है। इसे 350cc J-सीरीज के नीचे रखा जाएगा।

सेमीकंडक्टर उद्योग में उभरते कैरियर पथ

विजय गर्ग

सेमीकंडक्टर उद्योग आधुनिक वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें चिप्स के डिजाइन, निर्माण और वितरण शामिल हैं, जिसे एकीकृत सर्किट के रूप में भी जाना जाता है

आईसी सेमीकंडक्टर सामग्रियों से बने इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं जो इंसुलेटर और कंडक्टरों के बीच विद्युत चालकता प्रदान करते हैं और कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कैमरा, स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव सिस्टम और औद्योगिक मशीनरी जैसे रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, आपने शायद चिप की कमी के बारे में सुना है। चल रही आपूर्ति श्रृंखला वसूली और अमेरिका के लिए धन्यवाद 2022 के चिप्स और विज्ञान अधिनियम, उद्योग पूरे जोरों पर है, संपन्न है, और चिप्स अर्धचालक करियर की मांग करने वाले मेहनती पेशेवरों की आवश्यकता है।

मई 2023 के सेमीकंडक्टर उद्योग संगठन के लेख के अनुसार, वैश्विक सेमीकंडक्टर की बिक्री 2022 में $ 574 बिलियन तक पहुंच गई, जिसमें यू.एस. $ 275 बिलियन के लिए बिक्री लेखांकन।

जैसे-जैसे उद्योग पलटाव जारी रखता है, इसे पेशेवरों को चल रही जरूरतों और नई वृद्धि का समर्थन करने की आवश्यकता होगी।

जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में वैश्विक अर्धचालक उद्योग में कई कंपनियां हैं, अन्य देश इस क्षेत्र पर हावी हैं, जिनमें जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड शामिल हैं।

सेमीकंडक्टर उद्योग में करियर यदि आपने अभी इस रोमांचक क्षेत्र में करियर पर विचार करना शुरू किया है, तो यह आपको कुछ कैरियर विशेषज्ञता को समझने में मदद कर सकता है जो आप सही फिट के लिए विचार कर सकते हैं।

यहां कुछ अर्धचालक उद्योग विशेषज्ञता हैं जिन पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं:

सिस्टम और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकास सिस्टम एकीकरण और परीक्षण गर्मी और बड़े पैमाने पर स्थानांतरण इमेजिंग और लिथोग्राफी प्रदर्शन इलेक्ट्रानिक्स मेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रॉन प्रकाशिकी बुनियादी नौकरी कर्तव्यों और समग्र आवश्यकताओं जबकि इस उद्योग में पेशेवरों के लिए कुछ कर्तव्य विशिष्ट करियर से संबंधित हैं, कुछ अतिव्यापी कौशल की भी आवश्यकता है:

सेमीकंडक्टर का उपयोग करके निर्मित उपकरणों को डिजाइन करना, विकसित करना और परीक्षण करना आईसी और अर्धचालक के डिजाइन और विनिर्माण प्रक्रिया का अनुकूलन चिप्स और अर्धचालक की उपज, विश्वसनीयता और प्रदर्शन में सुधार एकीकृत सर्किट डिजाइन और विकसित करना अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का संचालन और रखरखाव अर्धचालक उपकरणों के शिपमेंट के लिए उचित पैकेजिंग सुनिश्चित करना विपणन अर्धचालक उपकरण चिप्स और अर्धचालक का उपयोग करने के नए तरीके खोजने और विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) का संचालन करना रिलीज और शिपमेंट से पहले अर्धचालक उपकरणों का परीक्षण करके गुणवत्ता नियंत्रण और आश्वासन प्रदान करना आप अपनी भूमिका में उद्योग का समर्थन कैसे करेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप उद्योग का समर्थन कर सकते हैं। यदि आप विपणन जैसे क्षेत्र का पीछा करते हैं तो आपको सबसे तकनीकी, विज्ञान-आधारित कौशल की आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालांकि, आपको अभी भी उन उत्पादों की दृढ़ समझ रखने की आवश्यकता है जिन्हें आप विपणन करेंगे।

लेकिन आपके द्वारा चुना गया कोई भी रास्ता विकास बढ़ाने के लिए निर्धारित इस आकर्षक उद्योग का समर्थन करने में मदद कर सकता है।

सेमीकंडक्टर इंजीनियर एक अर्धचालक इंजीनियर के रूप में, आप अर्धचालक उपकरणों, एकीकृत सर्किट (आईसी, या माइक्रोचिप्स), सॉफ्टवेयर, मॉड्यूल और इंटरफेस और संरचनाओं को डिजाइन, विकसित और परीक्षण करने में मदद करेंगे। आप सर्किट डिजाइन, डिवाइस इंजीनियरिंग, या प्रक्रिया इंजीनियरिंग जैसे अध्ययनों में विशेषज्ञ चुन सकते हैं।

प्रोसेस इंजीनियर एक प्रोसेस इंजीनियर सेमीकंडक्टर उपकरणों का उत्पादन करने वाली विनिर्माण प्रक्रियाओं के विकास और अनुकूलन पर केंद्रित है। आपके काम में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, प्रक्रिया डिजाइन और अनुकूलन जैसे कारकों को समायोजित करके प्रदर्शन, उपज और विश्वसनीयता में सुधार करना शामिल होगा।

सत्यापन अभियंता एक सत्यापन इंजीनियर यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद बाजार में जारी होने से पहले ही कार्य करें। वे यह सत्यापित करने के लिए आईसी के मॉक संस्करण बनाते हैं और परीक्षण करते हैं कि वे प्रदर्शन विनिर्देशों और गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।

अर्धचालक विनिर्माण तकनीशियन इस कैरियर में, आप अर्धचालक उपकरणों के उत्पादन और असेंबली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उपकरण का संचालन और रखरखाव, उत्पादन प्रक्रियाओं की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण जांच का संचालन करेंगे।

एकीकृत सर्किट डिजाइनर यह अत्यधिक तकनीकी कैरियर विकल्प आईसी पर केंद्रित है, और आप सर्किट फ्रेमवर्क डिजाइन करने, चिप प्रदर्शन का अनुकूलन करने और चिप प्लेसमेंट असाइन करने के लिए वीएचडीएल या वेरिलॉग सहित टूल और प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करेंगे।

इस कैरियर के लिए वैकल्पिक नौकरी के शीर्षक में शामिल हैं:

हार्डवेयर इंजीनियर ASIC डिजाइन इंजीनियर पीसीबी लेआउट इंजीनियर सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इंजीनियर एक अर्धचालक पैकेजिंग इंजीनियर आईसीएस की भौतिक और विद्युत पैकेजिंग का समर्थन करने के लिए डिजाइन और विकास गतिविधियों को अंजाम देता है, विचार से सिमुलेशन तक अंतिम पैकेजिंग निर्णय। आप चिप्स की उचित सुरक्षा, इंटरकनेक्शन और थर्मल प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।

फील्ड सर्विस इंजीनियर अर्धचालक उद्योग में एक फील्ड सर्विस इंजीनियर (FSE) एक तकनीशियन है जो अर्धचालक प्रसंस्करण उपकरणों की स्थापना, रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। इस भूमिका में, आप नए उपकरण स्थापित करेंगे, मौजूदा उपकरणों का निवारण और मरम्मत करेंगे, ग्राहक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, और बहुत कुछ। आपको ग्राहकों और अन्य इंजीनियरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में भी सक्षम होना चाहिए।

टेस्ट इंजीनियर यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक अर्धचालक उपकरण जनता को बिक्री के लिए जारी होने से पहले कितनी अच्छी तरह काम करता है। एक परीक्षण इंजीनियर के रूप में, आप उपकरणों की कार्यक्षमता और प्रदर्शन को मापने, परीक्षण करने, परिणामों का विश्लेषण करने, समस्या निवारण मुद्दों और संतुष्ट होने तक पूरी प्रक्रिया को दोहराने के लिए परीक्षण विधियों को विकसित करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

बिक्री और विपणन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बिक्री और विपणन उपभोक्ताओं के लिए हर किसी की कड़ी मेहनत को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण घटक हैं। इस भूमिका में, आप निर्मित अर्धचालक उपकरणों को बढ़ावा देंगे और बेचेंगे, बाजार के अवसरों की पहचान करेंगे, ग्राहक संबंधों का निर्माण करेंगे, व्यावसायिक रणनीतियों का विकास करेंगे, और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करेंगे।

एक मेज के आसपास सहयोग करने वाले लोग

अनुसंधान और विकास (अनुसंधान एवं विकास) अनुसंधान एवं विकास में, आप नई अर्धचालक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए नई तकनीकों, सामग्रियों और डिवाइस फ्रेमवर्क का पता लगाएंगे। इस कैरियर में, आप अपने संगठन के लिए नए विचारों की ओर आपका और आपके व्यवसाय का मार्गदर्शन करने के लिए रुझानों, नवाचारों और भविष्य की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

अनुप्रयोग अभियंता एक एप्लिकेशन इंजीनियर के रूप में, आप अपने संगठन के अर्धचालक उपकरणों के उपयोगकर्ता अनुभव (यूएक्स) में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के साथ मिलकर काम करेंगे। आप अपनी खुद की अंतर्दृष्टि और सहानुभूति का उपयोग करेंगे क्योंकि आप अपने उत्पादों के साथ ग्राहकों की जरूरतों, इच्छाओं और निराशाओं को सुनते हैं। आप तकनीकी सहायता प्रदान करके भी उनकी मदद कर सकते हैं जो उन्हें अपने जीवन के सापेक्ष विभिन्न अनुप्रयोगों में अर्धचालक उत्पादों को एकीकृत करने की अनुमति देगा।

इस भूमिका में अपने काम के साथ, आप मौजूदा उत्पादों में सुधार और विस्तार करने में मदद कर सकते हैं।

आपूर्ति श्रृंखला और संचालन इंजीनियर यह विशेष काम शायद पिछले कुछ वर्षों से पेशेवरों के लिए असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन चूंकि उद्योग में चीजें दिख रही हैं, इसलिए दबाव शायद कम हो गया है।

एक आपूर्ति श्रृंखला और संचालन इंजीनियर के रूप में, आप अर्धचालक उत्पादों की योजना, सोर्सिंग, विनिर्माण, वितरण और वितरण की देखरेख करने के लिए काम करेंगे। इस नौकरी में प्राथमिक लक्ष्य दक्षता के अनुकूलन, लागत को कम करने और रसद के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

गुणवत्ता और विश्वसनीयता इंजीनियर एक गुणवत्ता और विश्वसनीयता इंजीनियर के रूप में, आप अर्धचालक उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता आश्वासन प्रदान करेंगे। आप परीक्षण प्रक्रियाओं को विकसित और लागू करेंगे।

अर्धचालकों में व्यवसायों के लिए वेतन ऊपर सूचीबद्ध करियर इस उद्योग में आपके पास मौजूद कई विकल्पों में से कुछ ही हैं। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (बीएलएस) के अनुसार, वेतन विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला को दर्शाता है, मुआवजा प्रदान करता है जो लगभग $ 52,000 से शुरू होता है और लगभग $ 177,000 तक जाता है।

उद्योग के भीतर कई कैरियर क्षेत्रों का अन्वेषण करें सेमीकंडक्टर उद्योग में आपके लिए बहुत सारे रोमांचक कैरियर के अवसर हैं।

पुल बने भाषा

विजय गर्ग

इसमें दो राय नहीं कि भाषाई विविधता रंग-बिरंगे फूलों की तरह भारत की खूबसूरती की वाहक है। वहीं यह विविधता देश की सांस्कृतिक समृद्धि का आधार भी है। यह विडंबना ही है कि राजनीतिक लाभ के लिये क्षेत्रीय भाषा के गौरव के नाम पर हिंदी विरोध का मोर्चा अकसर खोला जाता है। निस्संदेह समय-समय पर उभरने वाले विवाद क्षेत्रीय गर्व और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों को ही उजागर करते हैं। कुछ समय पहले ऐसे ही विवाद में मराठी को व्यवहार में न अपनाने के आरोप लगाकर एक अधिकारी को थप्पड़ मारने का विवाद सामने आया था। कालांतर भाजपा शासित राज्य में मराठी की अनिवार्यता कामकाज में लागू की गई थी। अब ताजा विवाद कर्नाटक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रबंधक के कन्नड़ में बात करने से इनकार करने पर उठा है। जिसका कहना था कि वह हिंदी भाषी है और हिंदी में वार्तालाप करेगा। इस प्रकरण में अधिकारी का तबादला व खासा विवाद हुआ। स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय भाषा की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल खासे सक्रिय हुए। इस बीच जन सेवा में भाषाई संवेदनशीलता के प्रशिक्षण की मांग भी उठी। वैसे भी केंद्रीय सेवाओं के रूप में काम करने वाले विभागों व बैंक आदि के कर्मचारियों व अधिकारियों के विभिन्न राज्यों में अकसर तबादले होते रहते हैं। यह संभव भी नहीं कि हर व्यक्ति हर राज्य की भाषा बोल सके, लेकिन सीधे तौर पर जन-सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य की स्थानीय भाषा का ही उपयोग उपभोक्ताओं से सहज संवाद के लिये करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बेंगलुरू में एक तकनीकी पेशेवर को हिंदी में बोलने के कारण पार्किंग की सुविधा से वंचित कर दिया गया। इस घटना ने गैर हिंदी भाषी इलाकों में भाषायी सहिष्णुता की बहस को नये सिरे से खड़ा किया। निश्चित रूप से दोनों ही घटनाएं भाषाई व सांस्कृतिक एकता के लिये चुनौती पेश करती हैं। जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

उल्लेखनीय है कि ये घटनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के त्रि-भाषा फार्मूले की पृष्ठभूमि में हुई हैं। दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को तीन भाषाएं सीखने की सलाह दी गई है। जिसमें कम से कम दो भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए। हालांकि, इस शैक्षिक नीति का मकसद बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है, लेकिन तमिलनाडु में इस नीति का प्रतिरोध सामने आया है। राजनीतिक दल इसे हिंदी थोपने और अपनी भाषाई पहचान के लिये खतरा बता रहे हैं। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विरोध की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। खासकर तब से जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की कवायद शुरू हुई थी। हालांकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लचीलेपन के साथ इस बात पर जोर देती रही है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। इसके साथ यह भी कि भाषाओं के चयन का मुद्दा राज्य, क्षेत्रों और छात्रों पर छोड़ दिया जाएगा। वहीं कतिपय राजनीतिक दल आरोप लगाते रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा का व्यावहारिक क्रियान्वयन एक विवादस्पद मुद्दा है। बहरहाल, इस मुद्दे पर क्षेत्रीय भाषाओं पर इसके प्रभाव और हिंदी के कथित प्रभुत्व को लेकर बहस चल रही है। बहरहाल, इस तरह के विवादों से आगे बढ़ने के लिये आपसी सम्मान और समझ का माहौल बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। सार्वजनिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनकी सेवाएं स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही कर्मचारियों व अधिकारियों को सांस्कृतिक और भाषाई संवेदनशीलता में प्रशिक्षित किया जाए। निस्संदेह, शैक्षिक नीतियों को पूरे लचीलेपन के साथ लागू किया जाना चाहिए। जिसमें बहुभाषी दक्षता को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। निस्संदेह, भारत की भाषाई बहुलता को एक विभाजनकारी कारक के बजाय एक एकीकृत शक्ति के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देश की विविध भाषाओं को सहानुभूति और खुलेपन के साथ अपनाकर, हम अपने राष्ट्र के ताने-बाने को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भाषा एक पुल बने, न कि एक बाधा।

कागज-पत्तर ढीले और पहुंच का रुतबा

विजय गर्ग

अपने यहां ऐसे भी दीवाने हैं जो कलाई पर घड़ी नहीं हेलमेट बांधते हैं। भारत में ट्रैफिक नियम उस प्रेमिका की तरह हैं जिनसे सब वादा करते हैं पर निभाता कोई नहीं। ट्रैफिक सिग्नल उस बुजुर्ग की तरह होता है जिसे सब सम्मान से देखते हैं, पर जिसकी मानता कोई नहीं। यहां सड़कों पर सबसे विश्वसनीय सहारा न तो हेलमेट है, न सीट बेल्ट, न ही गाड़ी के कागज और न ही ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे कारगर सुरक्षा कवच है- मोबाइल। एक बार अपने प्रभावशाली चाचा-मामा का मोबाइल मिलाकर ट्रैफिक पुलसिये को दे दो, बस सारी सिट्टीपिट्टी गुम हो जायेगी। ये फोन कॉल एक ऐसा महामंत्र है जिसे उच्चकोटि की भारतीय चालकों की आत्मा में संस्कार स्वरूप डाल दिया जाता है। बच्चा जब साइकिल छोड़ स्कूटी पर चढ़ता है तो मां कहती है- बेटा! ध्यान से चलाना और पिता कान में फुसफुसाते हैं कि कुछ हो जाये तो चाचा को फोन कर लेना।

भारत में अधिकांश गाड़ियां दो इंजन से चलती हैं- एक पेट्रोल या डीजल इंजन और दूसरा प्रभावशाली कनेक्शन इंजन। आम आदमी बेचारा कितना दयनीय प्राणी है! जिसके पास न तो विधायक या पार्षद चाचा-ताऊ का नंबर है, न अपने किसी परिचित उच्चाधिकारी का। ट्रैफिक पुलिस जब रुकवाती है तो चालक जेब से न तो ड्राइविंग लाइसेंस निकालता है, न आरसी या इंश्योरेंस। सबसे पहले वह मोबाइल निकालता है और तेजी से उंगलियां घुमाते हुए अपने परिचित का ताकतवर नाम ढूंढ़ कर कॉल मिलाता है। किसी पॉवरफुल आदमी से पहचान सचमुच अदृश्य बीमा है। ये अदृश्य बीमे हर नियम को सिर के ऊपर से कुदवा देते हैं।

देश सड़क पर नहीं बिगड़ता, देश उस मोबाइल कॉल से बिगड़ता है जिसमें कोई ड्राइवर गरजता है कि लो, बात करो मेरे विधायक चाचा से। जहां संबंधों से देश चलता हो, वहां कानून-कायदे मात्र एक बुकलेट बनकर रह जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस एक कन्फ्यूज्ड किरदार या यूं कहें कि किसी हिंदी सीरियल का जूनियर आर्टिस्ट बनकर रह जाती है। जब तक गाड़ियों में दस्तावेज़ कम और परिचय-पत्र ज्यादा मिलेंगे, तब तक सड़कें असुरक्षित रहेंगी और कानून हाशिये पर। यह देश तब बदलेगा जब 'कौन जानता है' कि जगह 'क्या सही है' पूछा जायेगा। अन्यथा आगे चालान कट रहे हैं पता चलते ही राहें पलटती रहेंगी और सिफारिशें चालान काटने वालों को चुप करवाती रहेगी।

गर्म सिंदूर वाला लहू

पहलगाम नरसंहार को एक माह बीत चुका है। उन मासूम, बेगुनाह लोगों के हत्यारे और बहन-बेटियों का सिंदूर उजाडने वाले पापी कहां हैं, यह सहज सवाल हमारे भीतर भी खदबदा रहा है। हम देश की सेना और सुरक्षा बलों के साहस, पराक्रम और जांच पर रत्ती भर भी सवाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 3000 संदिग्धों या आतंकियों के 'जयचंदों' से पूछताछ कर सुराग टटोलने की कोशिशें की हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं। बीते 10-12 दिनों में कुछ आतंकियों और घुसपैठियों को ढेर भी किया गया है। यह आलेख लिखने तक जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों की घेराबंदी की थी और मुठभेड़ जारी थी। खुफिया लीड थी कि जैश-ए-मुहम्मद के 3-4 आतंकी उस इलाके के जंगलों में छिपे हैं। दरअसल पहलगाम नरसंहार आज भी एक जिंदा और प्रासंगिक मुद्दा है। उसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर में लोगों को संबोधित करते हुए जो रौद्र रूप दिखाया है, वह अभूतपूर्व है और उसमें पहलगाम में सिंदूर मिटाने, उजाडने की चिंता और आक्रोश भी निहित है। प्रधानमंत्री इसे गुस्सा या आक्रोश ही नहीं मानते, बल्कि समर्थ भारत का रौद्र रूप और न्याय का नया स्वरूप मानते हैं और यही 'ऑपरेशन सिंदूर' है। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि उनकी रगों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। 'जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। 'जब सिंदूर बारूद बन जाता है, तो उसके क्या नतीजे होते हैं, यह दुश्मन ने देख लिया है।' प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द अभिधात्मक नहीं हैं, बल्कि सिंदूर के प्रतीक के तौर पर लाक्षणिक हैं। प्रधानमंत्री अब भी पहलगाम और सिंदूर की त्रासदियों से जुड़े हैं। यह राजनीति नहीं है। कोई भी चुनाव सामने नहीं है। बिहार और राजस्थान के बीच व्यापक दूरियां हैं। बीकानेर के एयरबेस से कुछ ही दूरी पर, सीमापार, पाकिस्तान का रहीम यार एयरबेस है, जो ध्वस्त होने के बाद आईसीयू में पड़ा है। न जाने अब वह कब खुलेगा। प्रधानमंत्री ने देश को बताया है कि सिंदूर उजाडने का बदला लिया जा चुका है, प्रण पूरा किया गया है।

प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अब कोई आतंकी हमला भारत पर किया जाएगा, तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। हम आतंक और उसके सरपरस्तों को अलग-अलग नहीं समझेंगे, लिहाजा करारा जवाब पाकिस्तान, उसकी फौज और अर्थव्यवस्था को भी झेलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को यहां तक चेतावनी दी है कि उसे पाई-पाई को मोहताज कर दिया जाएगा। विडंबना यह है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस प्रधानमंत्री के संबोधन और सरोकारों को 'फिल्मी डॉयलॉग' करार दे रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री खोखले भाषण देना बंद करें। कैमरे के सामने ही आपका लहू गर्म क्यों होने लगता है? कांग्रेस लगातार सवाल दाग रही है कि जब हालिया संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान का बहुत कुछ तबाह कर दिया था, तो अचानक युद्धविराम क्यों किया गया? अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में युद्धविराम क्यों किया गया? आखिर हम पीओके तक पहुंच कर उसे वापस लेने में नाकाम क्यों रहे? ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जवाब विदेश मंत्रालय और हमारे डीजीएमओ दे चुके हैं। दरअसल आज के संदर्भ में 1971 का भारत-पाक युद्ध और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी प्रासंगिक हैं। 1972 में 'शिमला समझौते' के बाद तत्कालीन सैन्य फील्ड मार्शल जनरल सैम मॉनकशॉ ने इंदिरा गांधी के सामने जो टिप्पणी की थी, हम उसे लिख नहीं सकते। अलबत्ता कांग्रेस बखूबी जानती है कि तब युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 से अधिक फौजियों के आत्मसमर्पण के बावजूद भारत पीओके को अपने कब्जे में क्यों नहीं ले सका था? युद्धविराम का सवाल तब भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से किया गया था। बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप की विश्वसनीयता पर खुद अमरीका की रपट है कि उनके पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ने 30,573 झूठे या भ्रामक दावे किए थे। इस बार भी वह 8-10 बार बयानों को बदल चुके हैं। कांग्रेस को किसका भरोसा होगा कि युद्धविराम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बहरहाल पहलगाम आज भी एक राष्ट्रीय मुद्दा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने आतंकवाद का फन कुचलने की दमदार नीति और रीति दिखाई है। एकजुट होकर चलने की जरूरत है।

लाहुल में बांध, जरा संभल कर

यदि वहां की संवेदनशील ढलानों में भूस्खलन से तबाही शुरू हो गई तो इन लोगों की रोजी पर भी संकट पैदा हो सकता है। हिमालय में सामान्य से एक अंश ज्यादा तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, और इसमें बांध जनित मीथेन गैस का भी योगदान माना जा रहा है

लाहुल, हिमाचल प्रदेश के जिला लाहुल-स्पीति का पश्चिमी भाग है। जिला को कुंजुम दर्रा दो भागों में बांटता है। पूर्वी ओर स्पीति क्षेत्र पड़ता है जिसका पनढल सतलुज की ओर है, जबकि लाहुल का पनढल उसकी विपरीत दिशा में जम्मू कश्मीर की ओर है। चंद्रभागा इस घाटी के जलागम की निकास प्रणाली है। चंद्रभागा का उद्गम बड़ा शिन्ग्री हिमनद से होता है, जहां इसे चंद्रा नदी ही कहते हैं। नीचे तांदी में जब चंद्रा नदी के साथ भागा नदी का सम्मिलन हो जाता है, तो इसका नाम चंद्रभागा हो जाता है, और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर इसे चिनाब कहा जाता है। लाहुल से पश्चिम की ओर चंद्रभागा के निचले हिस्से में जिला चंबा का पांगी क्षेत्र पड़ता है। 1966 में राज्य पुनर्गठन से पहले लाहुल घाटी की उदयपुर तक की पंचायतें जिला चंबा का हिस्सा होती थीं, क्योंकि ये अंग्रेजी शासन काल में चंबा स्टेट का हिस्सा थीं। जब हिमाचल का गठन हुआ तो चंबा स्टेट पूरी की पूरी हिमाचल में मिल गई, किन्तु बाकी का लाहुल पंजाब का हिस्सा रहा। तब उदयपुर के नीचे के लाहुल को छोटा लाहुल या चंबा-लाहुल कहा जाता था और बाकी के लाहुल को ब्रिटिश लाहुल या बड़ा लाहुल कहा जाता था। लाहुल की भूगर्भीय स्थिति बड़ी ही नाजुक है। यह ट्रांस हिमालय में गिना जा सकता है। इसकी ढलानें बहुत ही कच्ची हैं और थोड़ी भी बारिश में बह जाने वाली हैं। वैसे तो इस भौगोलिक परिस्थिति में बारिश बहुत ही कम होती है। वर्ष भर में केवल 6.7 इंच बारिश होती है, वह भी ज्यादातर बर्फ के रूप में।

यहां का जलवायु शीत मरुस्थलीय है, किन्तु मिट्टी बहुत उपजाऊ है और विशेषकर बेमौसमी उपज सब्जी, आलू और मटर आदि के लिए बहुत उपयोगी है। यहां का आलू पूरे देश में प्रसिद्ध है और बंगाल तक बीज का आलू यहां से निर्यात होता है। पिछले कुछ वर्षों से मटर की खेती काफी बढ़ी है और यहां की गोभी भी अब अपनी पहचान बना चुकी है। जलवायु परिवर्तन के दौर में तापमान में वृद्धि के चलते यहां भी अब सेब की बागबानी होने लगी है, जबकि पहले यहां का जलवायु सेब के लिए ज्यादा ठंडा था। यह क्षेत्र भूकम्पीय दृष्टि से जोन 5 में पड़ता है, जो अति संवेदनशील श्रेणी में आता है। यह घाटी ग्लेशियरों से भरपूर है। बड़ा शिन्ग्री, छोटा शिन्ग्री और घेपनघाट प्रमुख ग्लेशियर हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि के चलते इन हिमनदों के पिघलने की गति बढ़ती जा रही है। हिमनदों के टूट कर संकरी घाटियों में गिरने के कारण झीलें बन जाती हैं। उनमें पानी जमा होता रहता है। जब पानी उन कच्चे मलबे के बांधों की ताकत से ज्यादा हो जाता है तो ये झीलें टूट जाती हैं और आकस्मिक बाढ़ों का कारण बनती हैं। 90 के दशक में पारछू नदी में तिब्बत में हिमनद झील के टूटने से आई बाढ़ ने हिमाचल में अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति बना दी थी और भारी नुकसान झेलना पड़ा था। पिछले दो वर्षों में भी हिमाचल में हिमनद पिघलने से बनी झीलों के टूटने के कारण आई बाढ़ों से भारी जन-धन की हानि हुई है, जिससे अभी तक भी प्रदेश उबर नहीं पाया है। गत दिनों राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र हैदराबाद ने हिमालय में 28043 हिमनद झीलों के होने की बात कही है। इनमें से बहुत सी झीलें हिमनद पिघलने की गति तेज होने के कारण आकार में बढ़ती जा रही हैं, जो कभी भी फूट कर निचले क्षेत्रों में भारी बाढ़ का कारण बन सकती हैं।

लाहुल के घेपन घाट हिमनद से बनी झील विशेषकर खतरनाक मानी जा रही है। एक अमरीकी अध्ययन संस्थान ने बताया है कि यह झील जो 14000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, पिछले वर्षों में आकार में बहुत बड़ी हो गई है। 1989 में यह 36.49 हेक्टेयर में फैली थी और अब 2023 में इसका आकार बढ़ कर 101.30 हेक्टेयर हो गया है। बड़ा शिन्ग्री हिमनद में भी ऐसी कई झीलें हैं जो आने वाले समय में खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। बड़ा शिन्ग्री हिमनद गंगोत्री हिमनद के बाद हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। इस संवेदनशील क्षेत्र में कई जल विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। यह घाटी आज तक जलविद्युत के लिए दोहन से बची हुई थी, किन्तु अब इसी पर दृष्टि गड़ चुकी है। हाल ही में हिमाचल ने तेलंगाना से दो परियोजनाओं के लिए निर्माण समझौते किए हैं। कुछ निर्माणाधीन हैं। यानी लाहुल से पांगी घाटी तक परियोजनाओं का जाल बिछने वाला है। इनमें से जिस्पा, शंलिंग, सटीगरी, छतडू, मयाड, तांदी, राशेल, सेली, टेलिंग, बदरंग, तिंगरेट, कोकसर, पुर्थी, साच खास और डूगर प्रमुख हैं। लाहुल घाटी कच्चे मलबे पर बसी हुई घाटी है। इसलिए स्थानीय समुदाय इतने बड़े पैमाने पर इस संवेदनशील घाटी में बृहद निर्माण कार्य से होने वाली उखाड़ पछाड़ से डरे हुए हैं कि कहीं उनका हाल भी इसी घाटी के लिंडूर गांव जैसा न हो जाए, जो बिना बारिश के ही भूस्खलन की चपेट में आ चुका है और जहां के वासियों को दूसरी जगह बसाने की जरूरत आन पड़ी है। इसलिए सरकार को इस दिशा में बढने से पहले इस पूरे इलाके का भूगर्भीय अध्ययन करवा लेना चाहिए। बांधों की योजना बनाने में ज्यादातर इंजीनियरिंग ज्ञान का ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी सीमाएं भी दिखने लग पड़ी हैं।

किन्नौर के उदाहरण से भी सीखने की जरूरत है। उर्नी ढांक के भूस्खलन के सामने सारी इंजीनियरिंग धरी रह गई है। लाहुल क्षेत्र बेमौसमी सब्जी आदि का उत्पादक क्षेत्र है, जिसके कारण काफी समृद्ध भी है। यदि वहां की संवेदनशील ढलानों में भूस्खलन से तबाही शुरू हो गई तो इन लोगों की रोजी पर भी संकट पैदा हो सकता है। हिमालय में सामान्य से एक अंश ज्यादा तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, और इसमें बांध जनित मीथेन गैस का भी योगदान माना जा रहा है। जल विद्युत के लिए बने बांधों की झीलों में जैविक पदार्थों के ऑक्सीजन रहित सडन से मीथेन गैस पैदा होती है जो कार्बन डाईआक्साइड से भी सात गुणा ज्यादा तापमान वृद्धि का कारण होती है, जिससे लाहुल घाटी में यदि सामान्य से ज्यादा तापमान वृद्धि होती है तो बारिश के दौर में भी वृद्धि हो सकती है, जिसके लिए यहां की धरती बनी नहीं है। बारिश यहां भूस्खलन का बड़ा कारण बन सकती है।

राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स सम्मिट 23-24 मई 2025 का आगाज़-एक्ट ईस्ट ,एक्ट फास्ट ,एक्ट फर्स्ट

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ को मालूम है कि भारत में प्राकृतिक संपदा, संस्कृति, संस्कारों, मानवीय बौद्धिक कौशलता,धार्मिक धर्मनिरपेक्षता, हर जाति धर्म, सहित राज्य स्तरपर हर त्योहार व सांस्कृतिक समारोह विशालता से मिलजुल कर मनाए जाते हैं। आज हम इस विषय पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि २३-२४ मई २०२५ को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर भारत के सात बहनों व एक भाई यांने असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा और एक भाई सिक्किम मिलकर राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स सम्मिट मनाए हैं, जिसका उद्घाटन २३ मई २०२५ को देरशाम माननीय पीएम ने किया था ।राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट २०२५ एक दो दिवसीय कार्यक्रम है,जो २३ और २४ मई को आयोजित किया है। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के एजेंडेमें मंत्रिस्तरीय सत्र, बिजनेस -टू-गवर्नमेंट(बीटूजी) और बिजनेस -टू-बिजनेस (बीटूबी) बैठकें और एक समर्पित प्रदर्शनी क्षेत्र शामिल हैं। निवेश संवर्धन के लिए पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में पर्यटन और आतिथ्य, कृषि- खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध उद्योग, वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास आईटी और आईटी-सक्षम सेवाएं, बुनियादी ढांचा और रसद, ऊर्जा,साथ ही मनोरंजन और खेल शामिल हैं ।चूँकिदेश को जल्द ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के सेमी कंडक्टर संयंत्र में निर्मित पहली 'मेड इन इंडिया' चिप मिलेगी। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स सम्मिट २३-२४ मई २०२५ का आगाज़- एक्ट ईस्ट,एक्ट फास्ट,एक्ट फर्स्ट इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,पूर्वोत्तर भारत 7 बहने एक भाई=अष्टलक्ष्मी-भारत का बेहतर भविष्य बनाने में अहम सहयोगी जो भारत के विज़न २047 को गति देगा।

साथियों बात अगर हम माननीय पीएम द्वारा उद्घाटन समारोह में संबोधन की करें तो, पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में प्रस्तुत करने, वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करने तथा प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से पीएम ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। दुनियाँ के सबसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति को रेखांकित करते हुए,उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर हमारे विविध राष्ट्र का सबसे विविध क्षेत्र है ।उन्होंने व्यापार, परंपरा, वस्त्र और पर्यटन में फैली विशाल संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र की विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर एक संपन्न जैव-अर्थव्यवस्था और बांस उद्योग,चाय उत्पादन और पेट्रोलियम, खेल और कौशल के साथ-साथ इको-टूरिज्म के लिए एक उभरते हुए केंद्र का पर्याय है। उन्होंने आगे कहा कि यह क्षेत्र जैविक उत्पादों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और ऊर्जा के एक पावरहाउस के रूप में खड़ा है। उन्होंने पुष्टि की कि पूर्वोत्तर अष्टलक्ष्मी का सार है, जो समृद्धि और अवसर लाता है। उन्होंने कहा कि इस ताकत के साथ, हर पूर्वोत्तर राज्य निवेश और नेतृत्व के लिए अपनी तत्परता की घोषणा कर रहा है ।विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्वी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने पूर्वोत्तर को इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक बताया। उन्होंने कहा, हमारे लिए, पूर्वी क्षेत्र सिर्फ एक दिशा नहीं है, बल्कि एक दृष्टि है-सशक्त बनाना, कार्य करना, मजबूत बनाना और बदलाव लाना - जो इस क्षेत्र के लिए नीतिगत रूपरेखा को परिभाषित करता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस दृष्टिकोण ने पूर्वी भारत, विशेष रूप से पूर्वोत्तर को भारत के विकास पथ के महत्वपूर्ण केंद्र में रखा है।

साथियों बात अगर हम पीएम द्वारा कही गई सबसे बड़ी पांच बातों की करें तो (1) विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरुरी है। नॉर्थईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए ; ईएएसटी का मतलब है - इमपावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म,पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की

नीति है। (२) आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने 700 से ज्यादा बार नॉर्थईस्ट गए हैं और रात भर वहां रुके हैं। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। (३) हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है ।हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले। एक समय था जब पूर्वोत्तर को सीमांत क्षेत्र माना जाता था। आज, यह भारत की विकास गाथा में अग्रणी के रूप में गर्व से खड़ा है। (4) एक तरह से नॉर्थईस्ट टूरिज्म के लिए एक कम्पलीट पैकेज है। अब नॉर्थईस्ट में विकास का लाभ कोने-कोने तक पहुंच रहा है, तो इसका भी पॉजिटिव असर टूरिज्म पर पड़ रहा है। वहां पर्यटकों की संख्या दोगुनी हुई है। (5) हमारा फोकस नॉर्थईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए। युवाओं को विकास की मुख्यधारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10 हजार से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है। बता दें यह कार्यक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है,आठ पूर्वोत्तर राज्य- असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, ऐसे राज्य हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी या समृद्धि के आठ रूप कहा जाता है ।यानि इसका कनेक्शन सेवन सिस्टर (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) से भी है, ये भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने- बाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ।अष्टलक्ष्मी महोत्सव क्षेत्र की प्रगति को प्रदर्शित करने,इसकी सांस्कृतिक संपदा का जश्न मनाने और भविष्य के विकास के लिए नए निवेश को आमंत्रित करने के लिए आयोजित होने वाला एक अहम कार्यक्रम है।

साथियों बात अगर हम माननीय पीएम उद्घाटन संबोधन में अष्टलक्ष्मी के वर्णन की करें तो हमारी परंपरा में मां लक्ष्मी को सुख, आरोग्य और समृद्धि की देवी कहा जाता है। जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है,तो हम उनके आठ रूपों को पूजते हैं। आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी,गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी और विद्यालक्ष्मी इसी तरह भारत के पूर्वोत्तर में आठ राज्यों की अष्टलक्ष्मी विराजमान हैं। नॉर्थ ईस्ट के आठों राज्यों में अष्टलक्ष्मी के दर्शन होते हैं ।अब जैसे पहला रूप है आदि लक्ष्मी। हमारे नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में आदिसंस्कृति का सशक्त विस्तार है ।नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में, अपनी परंपरा अपनी संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है। मेघालय का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, नागालैंड का हॉर्नबील फेस्टिवल, अरुणाचल का ऑरेंज फेस्टिवल,मिज़ोरम का चपचार कुट फेस्टिवल, असम का बीहू, मणिपुरी नृत्य ।दूसरी लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, यानि प्राकृतिक संसाधन का भी नॉर्थ ईस्ट पर भरपूर आशीर्वाद है ।आप भी जानते हैं,नॉर्थ ईस्ट मेंखनिज तेल, चाय के बागान और बायो-डायवर्सिटी का अद्भुत संगम है ।वहां रीन्युएबल एनर्जी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है ।धन लक्ष्मी का ये आशीर्वाद, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए वरदान है। तीसरी लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी की भी नॉर्थ ईस्ट पर भरपूर कृपा है। हमारा नॉर्थ ईस्ट, नैचुरल फार्मिंग के लिए, जैविक खेती के लिए, मिलेट्स के लिए प्रसिद्ध है ।हमें गर्व है किसिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। नॉर्थ ईस्ट में पैदा होने वाले चावल, बांस, मसाले और औषधीय पौधे,वहां कृषि की शक्ति को दिखाते हैं। आज का भारत,दुनियाँ को हेल्दी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए, न्युट्रिशन से जुड़े हुए, जो सोल्यूशन देना चाहता हैउसमें नॉर्थ ईस्ट की बड़ी भूमिका है ।अष्टलक्ष्मी की चौथी लक्ष्मी हैं,गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी कमल पर विराजमान हैं और उनके आसपास हाथी हैं ।हमारे नॉर्थ ईस्ट में विशाल जंगल हैं,काजीरंगा मानस मेहाओ जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वहां अद्भुत गुफाएं हैं,आकर्षक झीलें हैं। गजलक्ष्मी का आशीर्वाद नॉर्थ ईस्ट को दुनिया का सबसे शानदार टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का सामर्थ्य रखता है ।पांचवीं लक्ष्मी हैं, संतान लक्ष्मी यानि उत्पादकता की, क्रिएटिविटी की प्रतीक। नॉर्थ ईस्ट,क्रिएटिविटी के लिए स्किल के लिए जाना जाता है। जो लोग यहां एग्ज़ीबिशन में जाएंगे, हाट- बाज़ार में जाएंगे ।उन्हें नॉर्थ ईस्ट की क्रिएटिविटी दिखेगी। हैंडलूम्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का ये हुनर सबका दिल जीत लेता है ।असम का मुगा सिल्क मणिपुर का मोइरांग फी, वांखेई फी, नागालैंड की चाखेशांग शॉल। ऐसे दर्जनों हैं जो नॉर्थ ईस्ट की क्राफ्ट को, क्रिएटिविटी को दिखाते हैं ।अष्टलक्ष्मी की छठी लक्ष्मी है वीर लक्ष्मी ।वीर लक्ष्मी यानि साहस और शक्ति का संगम। नॉर्थ ईस्ट, नारी-शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक है। मणिपुर का नुपी लान आंदोलन, महिला- शक्ति का उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं ने कैसे गुलामी के विरुद्ध बिगुल फूंका था, ये हमेशा भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज रहेगा। रानी गाइदिन्ल्यु, कनकलता बरुआ, रानी इंदिरा देवी, ललनु रोपिलियानी लोक- गाथाओं से लेकर हमारी आज़ादी की लड़ाई तक,नॉर्थ ईस्ट की नारीशक्ति ने पूरे देश को प्रेरणा दी है। आज भी इस परंपरा को नॉर्थ ईस्ट की हमारी बेटियां समृद्ध कर रही हैं। यहां आने से पहले मैं जिन स्टॉल्स में गया, वहां भी अधिकतर महिलाएं ही थीं। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं की इस उद्यमशीलता से पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक ऐसी मजबूती मिलती है, जिसका कोई मुकाबला नहीं ।अष्टलक्ष्मी की सातवीं लक्ष्मी हैंजय लक्ष्मी। यानि ये यश और कीर्ति देने वाली हैं ।आज पूरे विश्व में भारत प्रति जो उम्मीदें हैं, उसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट की अहम भूमिका है। आज जब भारत, अपने कल्चर, अपने ट्रेड की ग्लोबल कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहा है तब नॉर्थ ईस्ट, भारत को साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के असीम अवसरों से जोड़ता है ।अष्टलक्ष्मी की आठवीं लक्ष्मी है,विद्या लक्ष्मी यानि ज्ञान और शिक्षा। नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिल चुका है। देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में ही बन रही है। मैरी कॉम, बाइचुंग भूटिया,मीराबाई चानू, लोवलीना, सरिता देवी ऐसे कितने ही स्पोर्ट्स पर्सन नॉर्थ ईस्ट ने देश को दिए हैं। आज नॉर्थ ईस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्ट अप्स, सर्विस सेंटर्स और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों में भी आगे आने लगा है। इनमें हज़ारों नौजवान काम कर रहे हैं। यानि "विद्या लक्ष्मी" के रूप में ये रीजन, युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल का बड़ा केंद्र बन रहा है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स सम्मिट २३-२४ मई २०२५ का आगाज़-एक्ट ईस्ट,एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट ।देश को जल्द ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के सेमीकंडक्टर संयंत्र में निर्मित पहली 'मेड इन इंडिया' चिप मिलेगी ।पूर्वोत्तर भारत 7 बहने एक भाई= अष्टलक्ष्मी -भारत का बेहतर भविष्य बनाने में अहम सहयोगी जो भारत के विज़न २047 को गति देगा।

शिक्षक – हर सरकारी योजना का ब्रह्मास्त्र, सरकार का बहुपयोगी पुर्जा

यदि आज के युग में कोई प्राणी ऐसा है जो हर सरकारी संकट का 'वन-मैन आर्मी' बनकर उभरता है, तो वह न कोई सुपरहीरो है, न कोई जादूगर, बल्कि वही पुराना, घिसा-पिटा, चश्मा लगाए, किताबों के बोझ तले दबा शिक्षक है। जी हाँ, वही शिक्षक, जिसे कभी बच्चे 'मास्टर जी' कहकर पुकारते थे और जिसके हाथ में चॉक और डस्टर हुआ करते थे, आज वह सरकारी तंत्र का 'स्विस आर्मी नाइफ' बन चुका है। वह शिक्षक, जिसका मूल धर्म था ज्ञान बाँटना, अब हर उस काम में उलझा है जो सरकार के किसी भी दफ्तर में 'बाकी लोग' करने से कतराते हैं।शिक्षक, जो अब न तो केवल शिक्षक रहा, न ही केवल इंसान – वह एक बहुउपयोगी, बहु-कार्यक्षम, सरकारी 'ऑल-इन-वन' मशीन बन गया है।

कभी वह कक्षा में 'अ' से 'अनार' और 'ब' से 'बकरी' सिखाता था। बच्चे उसकी बातों को आँखें फाड़कर सुनते थे, और वह ब्लैकबोर्ड पर भविष्य की इबारत लिखता था। लेकिन अब? अब वह 'अ' से 'आधार कार्ड' और 'ब' से 'बायोमैट्रिक अटेंडेंस' सिखाता है – न बच्चों को, बल्कि सरकारी सिस्टम को। उसका ब्लैकबोर्ड अब डिजिटल हो चुका है, लेकिन उस पर लिखे नहीं जा रहे गणित के सूत्र या हिंदी की कविताएँ, बल्कि सरकारी योजनाओं के फॉर्म, सर्वेक्षण की डेडलाइन, और 'ऐप डाउनलोड' की गाइडलाइंस।शिक्षक का पेशा अब पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा; वह एक ऐसी मल्टी-टास्किंग मशीन है, जो सुबह स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, दोपहर में वोटर लिस्ट अपडेट करता है, और शाम को गाँव में जाकर टीकाकरण का प्रचार करता है। रात को? रात को वह सरकारी पोर्टल पर डेटा एंट्री करता है, क्योंकि "सिस्टम क्रैश होने से पहले डेटा सबमिट करना है।"

शिक्षक की यह हालत देखकर लगता है कि सरकार ने उसे एक अनोखा सुपरपावर दे दिया है – हर काम में फिट होने का। चाहे वह जनगणना हो, चाहे पोलियो अभियान, चाहे राशन कार्ड का सत्यापन, या फिर किसी मंत्री जी की रैली में भीड़ जुटाने का काम – शिक्षक हर जगह है। वह न कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसकी 'ना' को सरकारी तंत्र में 'हाँ' ही समझा जाता है। उसकी चुप्पी को सहमति, उसकी थकान को समर्पण, और उसकी मजबूरी को ड्यूटी मान लिया गया है। कभी-कभी तो लगता है कि शिक्षक की नियुक्ति ही इसलिए हुई है ताकि सरकार के हर उस काम को पूरा किया जाए, जिसके लिए कोई और कर्मचारी तैयार नहीं। वह अब शिक्षक कम, सरकारी तंत्र का 'जुगाड़' ज्यादा है।

और इस जुगाड़ का हाल देखिए! जिस शिक्षक ने कभी बच्चों को सपने देखना सिखाया, आज वह खुद सपने में भी सरकारी आदेशों की फाइलें देखता है। उसकी डिग्रियाँ, उसका अनुभव, उसकी योग्यता – सब कुछ अब इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी तेजी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है, कितने घरों में जाकर 'डिजिटल इंडिया' का प्रचार कर सकता है, या कितनी जल्दी किसी योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर सकता है। उसका मूल्य अब उसकी शिक्षण कला से नहीं, बल्कि उसकी मल्टी-टास्किंग क्षमता से मापा जाता है। और अगर कोई पूछे, "मास्टर जी, आप क्या पढ़ाते हैं?" तो वह हँसते हुए कहेगा, "पिछले हफ्ते मैंने आधार अपडेट करना पढ़ाया, इस हफ्ते टीकाकरण, और अगले हफ्ते शायद स्वच्छ भारत अभियान।" उसकी पहचान अब 'शिक्षक' नहीं, बल्कि 'बीएलओ', 'सर्वे ऑफिसर', या 'डेटा एंट्री ऑपरेटर' बन चुकी है।

शिक्षक दिवस पर उसे एक गुलाब मिलता है, कुछ तालियाँ मिलती हैं, और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में उसकी तारीफ हो जाती है। लेकिन बाकी 364 दिन? बाकी दिन वह सरकारी मशीनरी का वह पुर्जा है, जो बिना तेल-पानी के चलता रहता है। उसे न अतिरिक्त वेतन मिलता है, न प्रशिक्षण, और न ही कोई धन्यवाद। वह बस चलता रहता है, क्योंकि अगर वह रुका, तो सरकारी योजनाओं का पहिया रुक जाएगा। और जब शिक्षा की गुणवत्ता गिरती है, जब बच्चे परीक्षा में फेल होते हैं, तो सारा दोष उसी के सिर मढ़ दिया जाता है। लोग कहते हैं, "शिक्षक पढ़ाते ही नहीं!" लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उसे पढ़ाने का वक्त ही कब मिलता है? जब वह सुबह से शाम तक फॉर्म भरने, सर्वे करने, और रैलियों में ड्यूटी करने में व्यस्त है, तो वह बच्चों को क्या पढ़ाए? वह तो खुद ही 'सरकारी सिलेबस' का गुलाम बन चुका है।

कभी समाज उसे 'गुरु' कहता था, 'विद्या का मंदिर' का पुजारी मानता था। लेकिन आज वह उस मंदिर का चौकीदार, क्लर्क, और चपरासी – सब कुछ बन गया है। वह अब न ज्ञान बाँटता है, न भविष्य गढ़ता है – वह बस सरकारी तंत्र की खामियों को ढँकने का जुगाड़ बन गया है। और सबसे बड़ी विडंबना? जब वह थककर चूर हो जाता है, जब वह कहता है कि "मैं सिर्फ पढ़ाना चाहता हूँ," तो उसे जवाब मिलता है, "यह भी तो तुम्हारी ड्यूटी है!" ड्यूटी? ड्यूटी का यह अजीब सा जाल है, जिसमें फँसकर शिक्षक न तो शिक्षक रहा, न इंसान। वह बस एक सरकारी आदेशों का पालन करने वाला यंत्र बन गया है।

तो अगली बार जब आप किसी गाँव में, किसी कस्बे में, या किसी शहर के कोने में किसी को देखें जो पानी बाँट रहा हो, वोटर स्लिप दे रहा हो, या किसी सरकारी योजना का फॉर्म भर रहा हो, तो जरा गौर से देखिएगा। शायद वह कोई साधारण कर्मचारी नहीं, बल्कि वही शिक्षक है – जिसके कंधों पर न सिर्फ बच्चों का भविष्य है, बल्कि सरकार की हर नाकामी को ढोने की जिम्मेदारी भी। वह शिक्षक, जो अब 'अध्यापक' नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र का 'अल्टीमेट जुगाड़' बन चुका है। और अगर आप उसे देखकर हँस रहे हैं, तो रुकिए – क्योंकि यह हँसी उस सिस्टम पर है, जो एक शिक्षक को शिक्षक रहने ही नहीं देता।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत",

ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट: जागरूकता सबसे बड़ा हथियार

यह चिंताजनक है कि हम अभी तक कोविड-19 (कोविड महामारी) द्वारा मचाई गई तबाही को भूले भी नहीं हैं, कि भारत समेत एशिया के कुछ देशों में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। गौरतलब है कि चीन, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसकी वजह है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट जेएन.1, जो बहुत जल्दी फैलता है और अब इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि

संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट जेएन. 1 और उसके सब-वेरिएंट्स एलएफ 7 और एनबी 1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण तीसरी लहर में मामले बढ़े थे, लेकिन यह दूसरी लहर की तुलना में कम घातक थी। उस समय मृत्यु दर केवल 0.2 प्रतिशत थी। बहरहाल, चिकित्सकों का यह कहना है कि कोविड-19 का ये वायरल हर साल म्यूटेट हो जाता है और अभी इस वायरस के गंभीर होने की स्थिति नहीं दिख रही है। वास्तव में, अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे यह लगे कि नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाले हैं। फिर भी यह कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले समूहों मसलन बुजुर्गों और बच्चों के लिए परेशानी पैदा करने वाला हो सकता है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि इस साल, 2025 की शुरुआत में दो मुख्य वेरिएंट दुनिया भर में फैल रहे हैं एलपी .8.1 और एक्सईसी। पिछले कुछ हफ्तों में एशिया में कोविड-19 के इस नए वेरिएंट के मामलों में तेज़ी आई है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि भारत दुनिया की एक बड़ी आबादी वाला देश है। इतने बड़े देश में हाल फिलहाल कोरोना मामलों की संख्या मामूली लग सकती है लेकिन भारत को इस वायरस से सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि यह बात अलग है कि हमारे देश में हाल फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के केरल, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली में नए मामलों में इजाफा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम वैश्विक घटनाक्रम को देखते हुए पूरी तरह से इस वायरस के प्रति सचेत और जागरूक हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि हमारी सरकारें और हमारे देश का स्वास्थ्य विभाग लगातार इस वायरस के प्रति सतर्कता बरत रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार केरल में 182 सक्रिय मामले हैं, जिसमें कोट्टायम, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम जैसे जिले प्रमुख हैं, वहीं पर तमिलनाडु में 66 और महाराष्ट्र में 56 मामले हैं। बहरहाल, पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि कोरोना का प्रभाव समय के साथ फीका पड़ चुका है और वायरस कमजोर हो गया है, लेकिन रोग और दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये कभी भी घातक और खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। आज बढ़ते कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रहीं हैं तो राज्यों के अस्पतालों को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं ।स्वास्थ्य विभाग भी समय-समय पर एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सतर्क व जागरूक रहने की अपील कर रहा है और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने, प्रार्थना-सभाओं, पार्टियों, और सामाजिक आयोजनों को फिलहाल स्थगित रखने की सलाह दी गई है। सरकार और निजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज , पैथोलॉजी लैब को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ।अस्पतालों में बेड रिजर्व किए गए हैं। नया सब-वेरिएंट से पता चलता है कि वायरस अपना रूप बदलने और खुद को ढालने में सक्षम है, इसलिए इससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बचाव ही सबसे बड़ा इलाज भी है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज हम सभी वायरस की दुनिया में सांस ले रहे हैं ।इस साल अब तक भारत में कोरोना के 257 मामले सामने आ चुके हैं। अतः आज जरूरत इस बात की है कि हम वायरस के नए रूपों में सामने आने के साथ ही नई टीकाकरण नीति को अपनाएं। आज दुनिया के अनेक विकसित देश टीके की बूस्टर खुराक हर साल लगाने की पेशकश कर रहे हैं। हमारे देश में भी इस पर विचार किया जाना चाहिए। जागरूकता तो सबसे बड़ा हथियार है ही।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़,उत्तराखंड।

भर्ती में समानता की वापसी: सामाजिक-आर्थिक बोनस अंकों पर हाईकोर्ट की सख्ती

भारतीय लोकतंत्र का मूल मंत्र है – समान अवसर। लेकिन जब अवसरों की तुलना में विशेष सुविधाएं या बोनस अंक बांटे जाएं, तो यह उस मूल भावना को ही चोट पहुंचाता है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भर्ती प्रक्रियाओं में सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जा रहे अतिरिक्त अंकों (बोनस मार्क्स) को अवैध ठहराया और उन्हें रद्द करने का आदेश दिया। यह फैसला केवल एक कानूनी निर्देश नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं की उम्मीदों का न्यायिक जवाब है जो केवल मेरिट के आधार पर अपना हक मांग रहे थे।

प्रियंका सौरभ

भारतीय प्रशासनिक ढांचे में सामाजिक न्याय को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है, लेकिन इसके नाम पर समय-समय पर ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो समानता की भावना से टकराते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 2019 में सामाजिक-आर्थिक आधार पर 10 अतिरिक्त अंक देने की नीति इसी प्रकार का निर्णय था। यह नीति उन अभ्यर्थियों को लाभ देती थी जो या तो अनाथ हैं, विधवा मां के पुत्र हैं, परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है आदि। यद्यपि यह नीति सहानुभूति के आधार पर प्रेरित थी, लेकिन इससे मेरिट के सिद्धांत को गहरी चोट पहुंची। कई योग्य अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, वे इस ₹बोनस सिस्टम₹ के कारण बाहर हो गए।

संघर्ष की आवाज़: जो गला फाड़कर भी सुना नहीं गया

जब कोई छात्र 90 में से 90 अंक लाकर भी चयन से वंचित रह जाए, तो यह सिर्फ परीक्षा की असफलता नहीं, सिस्टम की विफलता होती है। और जब यह गड़बड़ी साफ दिखती हो लेकिन सब चुप हों – तो यह चुप्पी भी अपराध की साझेदार होती है। उस समय बहुतों ने सवाल नहीं उठाए, लेकिन कुछ लोगों ने आवाज़ बुलंद की। मैंने बोल-बोलकर अपना गला फाड़ लिया था कि यह सामाजिक-आर्थिक बोनस अंक प्रणाली असंवैधानिक है, और यह फैसला एक दिन पलटेगा – और उस दिन हजारों ज़िंदगियाँ प्रभावित होंगी। लेकिन उस समय वोट बैंक की राजनीति ने सबकी आंखों पर पर्दा डाल दिया।

"जो चयनित हुए, वे भी प्रताड़ित हुए, और जो नहीं हुए वे भी – सबको सज़ा मिली!"

मैंने सबसे पहले इस नीति पर संपादकीय लिखे। विरोध सहा, लेकिन बोलती रही। क्योंकि जानती थी – यह फैसला सबको ले डूबेगा। आज जब कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, तो वे बच्चे जीत गए हैं – जिन्होंने सालों तक नौकरी के अधिकार से वंचित होकर लड़ाई लड़ी। लेकिन जो चयनित होकर सेवा दे रहे थे – उनका क्या दोष? वे भी बलि चढ़ा दिए गए।

इस पूरी त्रासदी की जड़ है – वोट बैंक की घटिया राजनीति। पहले सहानुभूति के नाम पर नीतियां बनाईं, अब उनका खामियाज़ा भुगतने के लिए निर्दोष युवा छोड़ दिए।

₹बागड़ बिल्लोंर₹ का तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा – जो भी भुगते, सिर्फ आम छात्र। जो आज अधिकार लेकर खड़े हैं – उन्होंने वो अधिकार लड़कर लिया है, भीख में नहीं।

अब सवाल यह है कि उन कर्मचारियों का क्या होगा जो कोर्ट के फैसले के कारण बाहर होंगे? क्या उन्हें कोई पुनर्वास मिलेगा? क्या यह सिस्टम उनसे माफी मांगेगा?

गलत का परिणाम गलत ही होता है – और सही का सही। देर-सवेर ही सही। धिक्कार है ऐसी नीतियों पर, जिन्होंने हजारों को प्रताड़ित किया – और जिन्हें हक मिला, वह भी सिर्फ संघर्ष से मिला।

अदालत का हस्तक्षेप और स्पष्ट रुख

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस नीति को संविधान की भावना के विपरीत बताया। अदालत ने आदेश दिया कि: भविष्य में इस प्रकार के बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे।

जिन अभ्यर्थियों को इन अंकों के चलते नियुक्ति मिली, उन्हें वरिष्ठता सूची में नीचे किया जाएगा। तीन माह के भीतर नई मेरिट सूची बनाकर फिर से परिणाम घोषित किए जाएं।

यह निर्णय केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि न्याय की दिशा में एक नैतिक सुधार भी है।

बोनस अंकों के पीछे का आंकड़ा:

लगभग 25 से 30 हजार अभ्यर्थियों को इस नीति से लाभ हुआ। अनेक ऐसे मामले सामने आए जहाँ 90 में से 90 अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी चयन से बाहर हो गए, जबकि दूसरों को बोनस के कारण लाभ मिला। यह स्थिति न केवल अयोग्यता को बढ़ावा दे रही थी, बल्कि व्यवस्था में असंतोष भी भर रही थी।

सरकार की भूमिका और विरोधाभास

हैरानी की बात यह है कि हरियाणा सरकार ने पिछले वर्ष ही यह बोनस अंक देना बंद कर दिया था। परंतु पहले से हुई नियुक्तियों में इसे लागू नहीं किया गया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामले में ₹फैसला भविष्य में लागू होगा₹ जैसे बहाने स्वीकार्य नहीं होंगे, और जो नुकसान मेरिट पर आधारित अभ्यर्थियों को हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए।

वास्तविकता और व्यावहारिकता के बीच टकराव

सवाल यह है कि क्या ऐसे निर्णय व्यावहारिक हैं? जो लोग पिछले 2-3 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, क्या उन्हें नीचे किया जाएगा? क्या इससे प्रशासनिक ढांचे में अव्यवस्था नहीं फैलेगी? जवाब है – यदि शुरुआत ही गलत हो, तो व्यवस्था का टिकना अन्याय पर होगा। न्याय की गाड़ी को अस्थायी हानि सहकर भी सही ट्रैक पर लाना जरूरी है।

राजनीतिक चुप्पी और नौजवानों का असंतोष

यह विषय उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो बिना किसी विशेष लाभ के मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु दुर्भाग्य से अधिकांश राजनीतिक दल इस पर मौन हैं क्योंकि ये नीतियाँ अक्सर वोट बैंक को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। एक अभ्यर्थी की यह टिप्पणी इस स्थिति को बखूबी दर्शाती है:

"हमने मेहनत की, टॉप किया, फिर भी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि हम 'सामाजिक-आर्थिक रूप से विशेष' नहीं थे। अब कोर्ट ने हमारी बात सुनी है।"

भविष्य की दिशा क्या हो?

नीतियों की समीक्षा होनी चाहिए: किसी भी सरकारी नीति को लागू करने से पहले यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह समानता के सिद्धांत से मेल खाती है। बोनस अंक की बजाय विशेष प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, और परामर्श सुविधाएं दी जा सकती हैं ताकि पिछड़े वर्गों को सशक्त किया जा सके। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए।

हाईकोर्ट का यह निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली की एक बड़ी जीत है। यह उस वर्ग के लिए आशा की किरण है जिसे राजनीतिक नीतियों ने हाशिये पर ला दिया था। समानता का मतलब यह नहीं कि सभी को एक ही रेखा से दौड़ने दिया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी के पैर में कोई बेड़ी न हो। सामाजिक-आर्थिक आधार पर अंक देना, एक तरह से कुछ के पांव में चप्पल और कुछ को नंगे पांव दौड़ाने जैसा था। अब न्याय की अदालत ने सबके लिए समतल मैदान तय कर दिया है।

"ज़िंदगी की नक़ाबें"

ऐ ज़िंदगी, तू हर रोज़ इक नया चेहरा दिखा देती है,
अपनों की भीड़ में अजनबियों-सी हवा बहा देती है।
हर रिश्ते की पोटली में कुछ भ्रम, कुछ धोखे निकले,
हर मुस्कान के पीछे छुपे सौ-सौ रोखे निकले।

कभी जिसको अपना समझा, वही पराया निकला,
दिल के मंदिर में बसा देवता, साया निकला।
तेरे इम्तिहान की हद अब महसूस होती है,
हर सुबह एक नया ज़ख्म महसूस होती है।

कितनी बार और परखेगी, बता ओ ज़िंदगी,
कोई तो हो जो रहे बस सादगी में बंदगी।
क्या हर आंख की नमी को तू पहचान पाएगी?
क्या सबके चेहरे से नक़ाब हटाएगी?

ये चुप सी शामें, ये सिसकती रातें,
हर इंसान के भीतर छुपी हैं सौ सौ बातें।
तू तो सब जानती है, फिर अनजान क्यों बनी है?
अपनेपन की तलाश में तू भी थकी सी लगी है।

बस अब किसी के चेहरे पे मुस्कान रहने दे,
किसी के दिल में एक मकाम रहने दे।
हर बार हर किसी को आज़मा कर थक गई होगी,
अब किसी को तो बेनक़ाब अपना रहने दे, ऐ ज़िंदगी।

--- डॉ सत्यवान सौरभ

आकाश में तूफान, ज़मीन पर नफ़रत — फिर भी बच गई उड़ान

जब बादलों के गर्जन से आसमान दहल रहा हो, जहाज 36,000 फीट की ऊंचाई पर हिचकोले खा रहा हो, और यात्रियों की सांसे अटक गई हों — उस वक्त इंसान सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद करता है: इंसानियत। लेकिन 21 मई की शाम, जब दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई2142 जानलेवा तूफान में फंसी थी, तब उसे आसमान में हवा से ज़्यादा ज़रूरत ज़मीन पर बैठे इंसानों की समझदारी की थी। दुर्भाग्यवश, उस समझदारी की उम्मीद पाकिस्तान से थी।

यह फ्लाइट एक नियमित उड़ान थी। सब कुछ सामान्य था जब तक विमान पठानकोट के आसमान में नहीं पहुँचा। तभी पायलट के रडार पर एक भीषण तूफान दिखाई दिया — इतना विकराल कि उसकी लहरें आसमान को ही निगलने को तैयार थीं। सामान्य प्रक्रिया के तहत, ऐसे हालात में पायलट या तो तूफान से बचने के लिए वापस लौटता है या फिर वैकल्पिक रूट लेता है। लेकिन उस वक्त वापस लौटने की कोई संभावना नहीं थी। दायीं ओर तूफान था, और बाईं ओर पाकिस्तान का एयरस्पेस।

यह वह पल था जब ज़िंदगी और मौत के बीच एक पतली सी रेखा थी — और उसे पार कराने की चाबी थी पाकिस्तान के हाथ में। विमान के पायलट ने अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानवीय आधार पर लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर वैकल्पिक रास्ता देने की विनती की। यह एक औपचारिक नहीं, फौलादी मानवता की परीक्षा थी। लेकिन पाकिस्तान ने उस परीक्षा में बुरी तरह फेल होते हुए, इस अनुरोध को ठुकरा दिया।

इस एक फैसले ने 227 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दिया। यह केवल एक राजनीतिक इनकार नहीं था — यह मानवता के खिलाफ एक मौन अपराध था। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में किसी भी देश को मानवीय आधार पर मदद देने के लिए बाध्य होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की नीति स्पष्ट है — चाहे मामला ज़िंदगी का हो या शांति का, उसका एजेंडा सिर्फ ₹विरोध₹ है।

यह वही पाकिस्तान है जिसने पहले भी बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत से दुश्मनी की आग में अपने आसमान को बंद कर दिया था। उसी नीति का एक और उदाहरण इस घटना में सामने आया। सुरक्षा के नाम पर, पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को भारत के लिए बंद रखा हुआ है, और अब उसी बंदिश ने यात्रियों की जान को खतरे में डाल दिया।

सोचिए, अगर उस दिन पायलट थोड़ी भी चूक कर जाता, अगर वह तूफान की ताकत को ठीक से आंक नहीं पाता, तो क्या होता? भारत के आकाश में एक त्रासदी लिख दी जाती। 227 परिवार शोक में डूब जाते। इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक हादसा नहीं होतीं, ये इतिहास बनती हैं - और ये इतिहास यह बताता कि जब जीवन दांव पर था, तो पड़ोसी देश ने पीठ फेर ली।

लेकिन इस त्रासदी में भी एक रोशनी की किरण थी — हमारे पायलट की साहसिकता, उसकी निर्णय क्षमता और ज़िम्मेदारी ने वह कर दिखाया जो शायद किसी चमत्कार से कम नहीं था। पायलट ने विमान की ऊंचाई को एडजस्ट किया, तूफान के बीच रास्ता खोजा, और अंततः विमान को श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया। उस क्षण, एक राष्ट्र की लापरवाही के विपरीत, एक नागरिक की सूझबूझ ने जानें बचाईं।

यह पूरा घटनाक्रम भारत को एक बहुत गहरा संदेश देता है — कि अब समय आ गया है जब हमें अपने नागरिक विमानों की सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीति से अलग करके देखना होगा। पाकिस्तान जैसे राष्ट्र, जो अमानवीयता की पराकाष्ठा पर उतर आए हों, उनके साथ किसी भी स्तर पर भरोसे का रिश्ता बनाए रखना, एक आत्मघाती नीति बन चुकी है।

क्या यह घटना हमें झकझोरने के लिए काफी नहीं? क्या भारत को अब भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के इस व्यवहार को अनदेखा करना चाहिए? क्या आईसीएओ जैसी संस्थाओं में इसकी शिकायत दर्ज कर, इसे एक केस स्टडी बनाकर दुनिया को पाकिस्तान की असलियत नहीं दिखानी चाहिए? अगर एक देश के नागरिक विमान को मानवीय संकट के समय सुरक्षित मार्ग भी न मिले, तो फिर ऐसे पड़ोसी के साथ शांति की कल्पना ही बेमानी है।

हर बार जब भारत संयम दिखाता है, पाकिस्तान उसे कमजोरी समझता है। हर बार जब हम बातचीत की पहल करते हैं, वो उसकी आड़ में नई साज़िशें रचता है। अब वक्त है कि पाकिस्तान को उसके ही अंदाज़ में जवाब दिया जाए - मगर शब्दों से नहीं, नीतियों से। उसकी हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान उजागर की जाए, और हर ऐसे कदम को कठघरे में खड़ा किया जाए जो मानवता के खिलाफ हो। जब एक पायलट जान की बाजी लगाकर नागरिकों को बचा सकता है, तो क्या एक देश अपने लोगों की सुरक्षा के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखा सकता?

यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी। यह एक इम्तिहान था - पायलट का, मानवता का, और पाकिस्तान के चरित्र का। एक बार फिर पाकिस्तान ने वही किया जो वह हमेशा करता है - संवेदनाओं का गला घोंटना। और भारत को अब यह तय करना है कि वह कब तक ऐसे ₹पड़ोसीपन₹ की कीमत अपने मासूम नागरिकों की सांसों से चुकाता रहेगा।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी

मतलब की दुनिया और रिश्तों का बदलता मिज़ाज

आज की दुनिया में इंसानियत और रिश्तों का रंग बहुत बदल गया है। हर तरफ़ एक अजीब सी खुदगर्ज़ी और मतलबपरस्ती का आलम है। ख़ून के रिश्ते, जो कभी सबसे मज़बूत और पाक माने जाते थे, अब अक्सर बेमानी और कमज़ोर से लगने लगे हैं। रिश्तों में वो गर्मजोशी, अपनापन और साथ निभाने का जज़्बा कहीं गुम हो गया है।

मुसीबत के लम्हों में जब इंसान को अपने अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब अक्सर वही लोग दूर नज़र आते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। हर कोई अपनी परेशानियों और तक़लिफों की दास्तान सुनाने में इतना मशगूल है कि दूसरों के दर्द और ज़रूरतों को महसूस ही नहीं कर पाता। ऐसा लगता है जैसे हर शख़्स अपने ही ग़मों का बोझ उठाए, दुनिया से बेख़बर चल रहा है।

इस बदलती हुई दुनिया में सच्चे रिश्ते और दोस्ती की तलाश एक मुश्किल काम हो गई है। अब रिश्तों की गहराई ख़ून से नहीं, बल्कि एहसास और वफ़ादारी से तय होती है। जो लोग मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें, वही असल रिश्तेदार और दोस्त कहलाते हैं। बाक़ी तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, जैसे मौसम बदल जाते हैं।

फिर भी, ज़िंदगी उम्मीद का नाम है। अगर कोई एक भी शख़्स ऐसा मिल जाए जो आपके दर्द को समझे, आपके साथ खड़ा हो, तो समझिए आपने इस मतलब की दुनिया में एक अनमोल रिश्ता पा लिया है।

डॉ. मुश्ताक अहमद
शाह सहज़ हरदा
मध्य प्रदेश एक्स जे

पिता का प्यार अनमोल और अद्वितीय होता है

बाप और सूरज दोनों की गर्मी बर्दाश्त कर लिया करो,

जब ये डूब जाएँ, तो फिर कुछ नहीं बचता जिंदगी में।

सूरज तो हर सुबह फिर से निकल आता है,

मगर बाप जब चला जाता है,

तो जिंदगी में सिर्फ खालीपन और दर्द ही रह जाता है।बाप की डाँट, उसकी फिक्र,

कभी-कभी उसकी सख्ती में भी उसका प्यार छुपा होता है।उसकी छाँव में ही तो हम सुकून से जीना सीखते हैं।जब तक बाप है,हर मुश्किल आसान लगती है।उसके जाने के बाद

जिंदगी में एक अधूरापन सा रह जाता है,

जैसे आसमान से सूरज ही गायब हो गया हो।

इसलिए,बाप की बातों, उसकी नाराज़गी,

और उसकी तपिश को भी प्यार से सह लेना चाहिए।क्योंकि जब वो नहीं रहेगा,

तो उसकी यादें ही रह जायेंगी जो दिल से कई ऐसे सवाल पूछेंगी जिनका जवाब मुमकिन न होगा।

पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। उसकी मौजूदगी में ही जीवन की असली रौनक है। उसकी कद्र करें, जब तक वो आपके साथ है।

बाप का प्यार एक बार चला जाए तो वह कभी लौटकर नहीं आता क्योंकि पिता की जगह और उनका स्नेह कोई दूसरा नहीं भर सकता,सूरज की तरह पिता हमारे जीवन को रौशन करते हैं, पर उनके जाने के बाद जीवन में एक खालीपन और अंधेरा सा छा जाता है, जिसे कोई और रोशनी दूर नहीं कर सकती पिता का प्यार अनमोल और अद्वितीय होता है,उसकी कमी पूरी जिंदगी महसूस होती है।

डॉ.मुश्ताक अहमद
शाह सहज
हरदा मध्य प्रदेश

चांद तकते रहने की मेरी आदत न गई।

गया बचपन बचपन की यादें न गई।
तूतो चला गया तेरी परछाई ना गई।
बचपन की यादें हैं, मैं वहां भी गया।
अमराई है वहीं,कहीं अमराई न गई।
खत तेरे हिफाज़त से रखे हैं,अब भी।
फुल सुख गए हैं मगर खुशबू न गई।
रातों को जागता रहता हूं मैं अभी भी।
चांद तकते रहने की मेरी आदत न गई।
वक्त मिल जाए तो मुश्ताक आजाओ।
इन आंखों से इंतजार की हसरत न गई।

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह
सहज़ हरदा मध्य प्रदेश .

धर्मेंद्र प्रधान ने ढेंकनाल जिला कमाक्षा नगर में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड
ओड़िशा

भूबनेश्वर : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को ढेंकनाल जिले के कामाख्यानगर में एक केंद्रीय विद्यालय सहित 133.65 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, वे केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त पहल हैं और ढेंकनाल जिले के विकास में काफी मददगार साबित होंगी।केंद्रीय मंत्री ने आज सबसे पहले कामाख्यानगर के बैसिंगा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 के कामाख्यानगर बाईपास से दुबुरी खंड तक लगभग 1.5 करोड़ रुपये की

लागत से बने ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। 10.65 करोड़ रु. इसके बाद उन्होंने कामाख्यानगर महिला महाविद्यालय परिसर में केन्द्रीय विद्यालय, कामाख्यानगर में अस्थायी परिसर का लोकार्पण किया तथा जंतारीबोल में 1.5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी। 30 करोड़ रु. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने ढेंकनाल के विकास के लिए ओडिशा सरकार की लगभग 93 करोड़ रुपये की 22 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।केन्द्रीय विद्यालय के अस्थायी परिसर में चालू शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 1 से 5 तक 240 विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधा मिलेगी। ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए 45,000 से अधिक पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं को शिशु बटिका में परिवर्तित कर दिया है। कामाख्यानगर सेंट्रल स्कूल में शिशु बाटिका में भी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। केवल मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा से ही छात्रों का व्यक्तिगत विकास होगा।

मेयर सुलोचना दास के नाम पर राजधानी के सभी थानों में क्षेत्रीय सुरक्षा फोरम से केस दर्ज की जाएगी

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड
ओड़िशा

भुबनेश्वर: क्षेत्रीय सुरक्षा मंच ने भुवनेश्वर की मेयर सुलोचना दास की बांग्लादेशी टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है। तदनुसार, राजधानी के सभी पुलिस स्टेशनों पर उनके नाम से केस दर्ज किया जाएगा। क्षेत्रीय सुरक्षा मंच के अध्यक्ष जगन्नाथ प्रधान ने इस संबंध में बड़ी घोषणा की है।क्षेत्रीय सुरक्षा फोरम ने मेयर की बांग्लादेशी टिप्पणियों का कड़ा विरोध किया है।₹जो लोग अतिक्रमण करेंगे उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा।₹ लेकिन उन बांग्लादेशियों को निर्वासित करना संभव नहीं है जो यहां हैं, जिनके पास आधार, राशन या वोटर कार्ड हैं और जो यहां नागरिक के रूप में रह रहे हैं।

उनकी अच्छी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। मेयर सुलोचना दास के इस तरह के बयान से राजधानी की राजनीति गरमा गई है। नीलाद्रि बिहार से लेकर राजमहल तक मेयर के विरोध की आग फैल रही है। महापौर श्रीमती के इस्तीफे की मांग को लेकर विभिन्न संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। दास पर बांग्लादेशियों के प्रति समर्थन व्यक्त करने का आरोप है। युवाओं ने काले झंडे दिखाए और महापौर पर काला कपड़ा फेंका। बीएमसी में विपक्ष की भूमिका में सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के नेताओं ने महापौर के भाषण की निंदा की और उनके इस्तीफे की मांग की।

महापौर श्रीमती. दास नीलाद्री बिहार के वार्ड नंबर 14 स्थित कार्यालय में शिकायत निवारण शिविर से लौट रही थीं, तभी कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया। युवा मेयर के वाहन की ओर दौड़े और नारे लगाने लगे, ₹बांग्लादेशी मेयर, इस्तीफा दो।₹ वह कार से बाहर निकले और उन युवकों से बात की। लेकिन युवाओं ने सीधे तौर पर मेयर को दोषी ठहराया और चेतावनी दी कि जब तक बांग्लादेशियों को भुवनेश्वर से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक इस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

मंच के अध्यक्ष जगन्नाथ प्रधान के नेतृत्व में राजमहल चैक से शिशु भवन चैक तक सैकड़ों लोग जुलूस में शामिल हुए और महापौर श्रीमती की निंदा की। दास की टिप्पणी और पुतला दहन की निंदा की। अध्यक्ष श्री प्रधान ने कहा कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ और अवैध बसावट देश और राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। इस कारण केंद्र और राज्य सरकारों ने उन्हें बेदखल करने की योजना तैयार कर ली है। मेयर द्वारा संवैधानिक पद पर रहते हुए कानून का मसौदा तैयार करते समय भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले बांग्लादेशियों का समर्थन करना निंदनीय और राष्ट्रविरोधी है। इसलिए मेयर को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। श्री प्रधान ने देश की जनता से बिना शर्त माफी मांगने की भी मांग की।

ट्रंप व रामाफोसा का टकराव...!

व्हाइट हाऊस में जब बैठे दो राष्ट्राध्यक्ष,
आमने-सामने हो रखते रहें अपना पक्ष।
इस वैश्विक मंच पर उभर रहा था तनाव,
ध्रुवीकरण व सत्ता के खेल में मनमुटाव।
वह क्षण एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं,
आरोप-प्रत्यारोप में सत्य का साथ नहीं।

व्हाइट हाऊस में जब बैठे दो राष्ट्राध्यक्ष,
आमने-सामने हो रखते रहें अपना पक्ष।
ट्रंप व रामाफोसा के बीच हुआ टकराव,
व्यक्तित्वों की भिड़ंत में देखते हैं तनाव।
आज की दुनिया में कूटनीति के स्वरूप,
तथ्यों की अनदेखी में उकसावे का रूप।

व्हाइट हाऊस में जब बैठे दो राष्ट्राध्यक्ष,
आमने-सामने हो रखते रहें अपना पक्ष।
ये ट्रंप में क्रेडिट लेने की बढ़ रहीं प्रवृत्ति,
पाक-साफ नहीं दिखती मन की ये वृत्ति।
वैश्विक नेतृत्व में ना संयम व समझदारी,
रामाफोसा के सामने ना चली होशियारी।

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्यप्रदेश)

कोचिंग संस्थान में आत्महत्या दुर्भावना पूर्ण है

हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

कोटा व अन्य जगह छात्र छात्राएं निराशा में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं।

खासकर सिर्फ इसी साल 5 महिने में 14 छात्र छात्राओं ने सिर्फ कोटा में ही क्यों आत्महत्या की यह बहुत गंभीर बात है ? तभी देश की सर्वोच्च अदालत ने राजस्थान सरकार को फटकार भी लगाई है। माननीय न्यायाधीश ने सही कहा ऐसे मामलों को क्यों हल्के में लिया जाता है। कोचिंग संस्थान ऐसे संवेदनशील मामलों में चुप्पी क्यों कर लेती है ।यह बच्चों के भविष्य का सवाल है। जीवन की आपाधापी में उन्हें मशीन मत बनाइए।

युवा वर्ग को को आत्महत्या जैसा कदम नही उठना चहिऐ, चाहें कितना भी दुख हो यह तकलीफ हो ,संघर्ष के रास्ते पर चलकर जीना सिखना ही मनुष्य का धर्म है । समाजिक स्तर पर हम सभी को अपने बच्चों के प्रति आशावान होना चाहिए। जब भी कठिनाइयां आये तो बस अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। दुख तकलीफ़ तो बहुत है दुनिया में पर ऐसे मुश्किल समय में दोस्तों से बात होना जरूरी है। समय कितना भी खराब हो पर अपनों के लिए आप आगे आओ। बातचीत करने से समस्या का हल हो जाता है , और दिल में दर्द नहीं रहता। बोलचाल हो तो दिमाग में ग़म नहीं होगा। इसलिए मैं यही सोचता हूं कि अकेले में भी मनुष्य अगर अपनों से

वार्तालाप करें तो मन के विकार दूर हो जातें हैं। युवा पीढ़ी व छात्र छात्राओं के आत्महत्या जैसे गलत कदमों को उठाने पर भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय भी कोचिंग संस्थानों पर अपनी निगरानी रखें। ऐसी गाईडलाइन बनाई जाएं जिससे युवाओं के मन में आत्महत्या जैसे इस तरह के ग़लत कदम नहीं उठाए । कोचिंग संस्थान में भी बच्चों में आत्म विश्वास जागने हेतु मिलजुल सकारात्मक कदम उठाए। बच्चों में नाकारात्मकता की और जाने वाले प्रतिस्पर्धा के रंग में युवा पीढ़ी को मत डालो। कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राओं को एक तराजू में नहीं तोला जाएं, और ना उन्हें पढ़ाई का दबाव बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो व निराशा में डुब जायेंगे और आत्महत्या जैसा ग़लत कदम उठाएंगे। ऐसा देखा जाता है कि अच्छे अच्छे पढ़ाई करने वाले 90 प्रतिशत लाने वाले बच्चे भी जिन्दगी से हार क्यों मान रहे हैं ? आत्महत्या के मामले में माता पिता और परिजनों को अपने बच्चों को प्रतिस्पर्धा या नम्बर की रैस में नहीं ले जाएं। उन्हें आजादी दे उनके पंखों को फैलने दो। बच्चों की इच्छाशक्ति को समझें तभी वह सफलता की सीढ़ी पर चलकर आगे बढ़ेंगे। आत्महत्या जैसा ग़लत कदम उठाने से बचाने हेतु हम सभी मिलकर प्रयास करें। क्योंकि यह समाज के लिए अभिशाप है।

जब हांसी पुलिस ने भाटला प्रकरण में रजत कल्सन व भाटला के पीड़ितों को झूठा फसाने के लिए सेशन जज का नाम इस्तेमाल कर कर दी झूठी रिपोर्ट

हाँसी (रजत कल्सन)

भाटला सामाजिक बहिष्कार मामले में दलितों की शिकायतों को ख़ारिज करने व एडवोकेट रजत कल्सन को नाजायज तरीके से झूठे केस में फंसाने व दबंगो को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए हांसी पुलिस के अधिकारियो ने बीजेपी नेता की सहायता से हिसार के सेशन जज के नाम पर झूठी रिपोर्ट तैयार कर किया बड़ा फर्जीवाड़ा किया है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने २० मार्च को एससी एसटी एक्ट के संबंध में एक फैसला दिया था जिसमें एससी एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग के चलते एससी एसटी एक्ट के कुछ प्रावधानों को कमजोर किया गया था।हालांकि सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है परंतु यहां हांसी पुलिस ने जो कारनामा किया है उससे तो यह पता चलता है कि पुलिस दलित अत्याचार मामले में दबंगों को फायदा पहुंचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है ।

ताजा मामला भाटला में सामाजिक बहिष्कार प्रकरण का है ।पिछले साल जुलाई में भाटला में सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया था जिस बारे थाना सदर हांसी में एक मुकदमा सात दबंग ग्रामीणों के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था ।भाटला के इस सामाजिक बहिष्कार के मामले में भाटला के तीन दलित ग्रामीणों ने एसपी हांसी व सेशन जज हिसार को सामाजिक बहिष्कार के बारे में शिकायतें दी थी जोकि सेशन जज साहब हिसार ने शिकायत मिलने के बाद उसे कार्रवाई के लिए एस. पी. हिसार को रेफर कर दिया था तथा एस. पी. हिसार ने उसे हांसी का मामला होने के चलते एस. पी. हांसी को फॉरवर्ड कर दिया था। जब काफी दिनों तक पीड़ित दलितों की दरख्वास्त पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उन्हें आरटीआई से मिले दस्तावेजों से पता चला कि हरियाणा पुलिस जिला हांसी के दो डीएसपी नरेंद्र कादियान व विजेंदर सिंह व एक इंस्पेक्टर उदयभान गोदारा व एक सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार सब इंस्पैक्टर तथा भाटला चौकी इंचार्ज ने इन शिकायतों को जांच किए बिना ही ख़ारिज कर दिया।

दलित पीड़ितों ने अलग से सी. एम. विंडो में भी शिकायत दायर की थी। आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों से पता चला कि पुलिस ने दलित ग्रामीणों की सामाजिक बहिष्कार की शिकायत ख़ारिज करते समय जो रिपोर्ट तैयार की उसमे इन अधिकारियों ने हिसार के सेशन जज का ₹वाला देते हुए लिखा कि सेशन जज ने उन्हें मौखिक आदेश जारी करके उन्हें दलितों की शिकायत पर कार्रवाई करने से मना किया है पुलिस की रिपोर्ट मे सेशन जज साहब का ₹वाला देते हुए यह भी लिखा है कि उनके आगामी आदेश तक दलितों की शिकायतों पर कोई कार्यवाही ना की जाए।

पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बहिष्कार के लिए अधिवक्ता रजत कल्सन को जिम्मेवार ठहराया। इस मामले में हांसी पुलिस ने अधिवक्ता रजत कल्सन पर कई मुकदमे भी दर्ज किए थे। मजे की बात यह है कि पुलिस की इस फर्जी रिपोर्ट को हांसी भाजपा के मंडल प्रभारी प्रवीण बंसल ने बतौर प्रख्यात नागरिक तस्दीक भी किया है। सेशन जज की इन्हीं काल्पनिक आदेशों का ₹वाला देकर दलितों की शिकायतों को ख़ारिज कर दिया गया है ।

पीड़ित दलितों के एडवोकेट रजत कल्सन ने कहा

आरटीआई से जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उन से यह पता चला है कि सेशन जज साहब हिसार ने तो दलितों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस को आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे परंतु पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर सेशन जज हिसार के तथाकथित मौखिक बयानों के आधार पर एक कैंसलेशन रिपोर्ट तैयार कर दी ताकि गांव के दबंगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया जा सके जब कि हिसार के सेशन जज ने कभी भी इस तरह के कोई बयान या आदेश दिए ही नही।

एडवोकेट कल्सन ने कहा कि अगर सेशन जज के निर्देशानुसार दलितों की शिकायतों पर उचित कानूनी कार्रवाई होती तो गांव के दबंगों जो सामाजिक बहिष्कार के जिम्मेदार है, के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होने व उनको जेल में जाने का ख़तरा था ।पुलिस ने वफादारी निभाते हुए उन्हें जेल जाने से बचाने के लिए सेशन जज के नाम का दुरुपयोग कर एक फर्जीवाड़ा कर एक रिपोर्ट तैयार कर दी ।हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने यह फर्जी रिपोर्ट तैयार कर सीएम विंडो पर भी अपलोड कर दी तथा और हांसी पुलिस की हिम्मत की बात है कि जब पीड़ित दलितों ने इस बारे हाईकोर्ट में याचिका दायर की तो हांसी पुलिस के इन अधिकारियों ने यही फर्जी रिपोर्ट हाईकोर्ट में भी सबमिट कर दी।

एडवोकेट रजत कल्सन ने बताया कि इस बारे माननीय सेशन जज साहब के समक्ष एक याचिका दायर की गई कि किस तरह से उनके नाम पर एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करके पीड़ितों की शिकायतों को ख़ारिज कर दिया गया है तथा दबंगों को फायदा पहुंचाया गया है। पीड़ित दलितों ने सेशन जज से उनकी शिकायतों पर मुकदमा दर्ज करने व दोषी उपरोक्त पुलिस अधिकारियो के ख़िलाफ़ कारवाई की मांग की है। सेशन जज साहब हिसार ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तुरंत याचिका पर संज्ञान लेते हुए उसे प्रशासनिक तौर पर डील करने व आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने पास रख लिया है जिस बारे सेशन जज साहब की आगामी कार्रवाई का इंतजार है ।

अधिवक्ता रजत कल्सन ने कहा कि वे भाटला के दलितों को न्याय दिलाने व दोषी पुलिस अधिकारियों पर कारवाई के लिए उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे व इनको सज़ा दिलाने का काम करेंगे ।गौरतलब है कि पिछले काफी समय से हांसी पुलिस की कार्यशैली दलितों पर अत्याचारों के मामलों में सवालो के घेरे में रही है व जब भी दलित संगठन इन पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करते है तो जाति विशेष की खाप पंचायतें इन पुलिस अधिकारियों के पक्ष में आकर खड़ी हो जाती है। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई के माह में भाटला के दलितों का गांव के दबंगों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया था जिस बारे काफी शोर शराबा हुआ था तथा हांसी पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई करने की बजाय दलितों पर ही मुकदमा दर्ज करने का काम किया था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail .com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023